घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 196- सोमवार 18 - मई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

नीट पेपर लीक मामला...
आरोपी टीचर कोर्ट में पेश 14 दिनों की सीबीआई कस्टडी

नई दिल्ली,17 मई 2026। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 से जुड़े कथित पेपर लीक मामले में जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मामले में गिरफ्तार 'पेपर-सेटिंग कमेटी' की सदस्य मनीषा मंधारे को अदालत में पेश किया गया, जहां जांच एजेंसी की दलीलों के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। सीबीआई के अनुसार मनीषा मंधारे परीक्षा के बॉटनी और जूलॉजी प्रश्नपत्रों के अनुवाद कार्य से जुड़ी थीं। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि इसी जिम्मेदारी के कारण उनकी पहुंच सीधे असली प्रश्नपत्रों तक थी। आरोप है कि उन्होंने इस गोपनीय व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए प्रश्नपत्र लीक करने में अहम भूमिका निभाई। जांच में यह भी सामने आया कि मंधारे अकेले काम नहीं कर रही थीं। सीबीआई के मुताबिक, उन्होंने पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया। एजेंसी ने दावा किया कि मंधारे ने प्रश्नपत्र शुभम नामक आरोपी को सौंपा, जिसने आगे इसे अन्य लोगों तक पहुंचाया। सीबीआई ने अदालत से कहा कि यह मामला केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार देश के कई प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार विभिन्न राज्यों में एक साथ छापेमारी और पूछताछ जारी है। इसी कारण आरोपियों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर पूछताछ करना आवश्यक है। अदालत ने इन दलीलों को गंभीर मानते हुए 14 दिन की रिमांड मंजूर कर ली। इस खुलासे ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों छात्र और अभिभावक निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, लेकिन इस मामले ने उस विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है। अब सभी की नजर सीबीआई जांच पर टिकी है कि वह इस पूरे रैकेट के अन्य आरोपियों और मास्टरमाइंड तक कब पहुंचती है।

राहुल गांधी का केंद्र पर हमला...
नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा

नई दिल्ली,17 मई 2026। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को नीट-यूजी 2026 में कथित गड़बड़ियों को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस सांसद ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की भी आलोचना की। नीट 2024: पेपर लीक हुआ। एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। सीबीआई ने जांच बिठाई। एक कमेटी बनाई गई। नीट 2026: पेपर लीक हुआ। उन्होंने एक्स पर कहा, एग्जाम कैंसिल हो गया। मंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। सीबीआई फिर से जांच कर रही है। एक और कमेटी बनेगी। पीएम से देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है - उनके जवाब दीजिए! पेपर लीक बार-बार क्यों हो रहे हैं? आप इस एग्जाम पेपर डिस्कशन पर बार-बार चुप क्यों रहते हैं? आप उस शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं हटा रहे जो बार-बार फेल हो रहा है? यह टिप्पणी नीट-यूजी 2026 परीक्षा को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आई है, जिसमें पेपर लीक होने और उसके बाद परीक्षा रद्द होने के आरोप लगे हैं। इस बीच, सीबीआई ने रविवार को आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और आगे की जांच के लिए 14 दिन की कस्टडी मांगी। मंधारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पैनल का हिस्सा हैं और उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया के लिए एक्सपर्ट और ट्रांसलेटर के तौर पर काम किया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि एनटीए द्वारा फॉलो किया गया पूरी प्रक्रिया जांच के दायरे में है।

भारत में निर्मित पहला सी-295 विमान उड़ान परीक्षण के लिए तैयार

वडोदरा,17 मई 2026। वडोदरा स्थित टाटा के एयरबस प्लांट में स्वदेशी निर्मित पहले एयरबस सी-295 विमान के तैयार होने के साथ भारत ने रक्षा विमानन निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत इस विमान को पहली उड़ान परीक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है। उप वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने हाल ही में प्लांट का दौरा कर सी-295 विमान की प्रगति की समीक्षा की। सी-295 विमान भारतीय वायु सेना के पुराने एवरो-748 बेड़े की जगह लेगा और सामरिक हवाई परिवहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। यह 70 सैनिकों, 48 पैराट्रूपर्स या चिकित्सा के लिए 24 स्ट्रेचर और सामान ले जा सकता है। 2 प्रैट एंड व्हिटनी पीडब्ल्यू127जी टर्बोप्रॉप इंजनों से लैस सी-295 दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों सहित छोटी और आधी तैयार हवाई पट्टियों से भी उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स द्वारा विकसित स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली होगी। यह प्रोजेक्ट भारत और स्पेन के बीच 21,935 करोड़ रुपये के 56 एयरबस सी-295 विमानों के समझौते का हिस्सा है। इनमें से 16 विमान स्पेन से उड़ान भरने की स्थिति में भेजे जा रहे हैं, जबकि शेष 40 विमानों का उत्पादन भारत में किया जा रहा है। बता दें कि वडोदरा स्थित अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने 28 अक्टूबर, 2024 को किया था।

केरल में वीडी सतीशन आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ...एक दशक बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी

वीडी सतीशन के साथ 11 मंत्री भी लेंगे शपथ,राज्यपाल को सौंपी सूची

तिरुवनंतपुरम,17 मई 2026। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 11 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। सतीशन ने रविवार शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और मंत्रियों की सूची भी सौंपी। आइए जानते हैं किन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। स्टेडियम में हजारों पार्टी कार्यकर्ता,राजनीतिक हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था की जा रही है। बारिश से बचाव के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय को भी समारोह में आमंत्रित किया गया है। सतीशन ने कहा कि गठबंधन के नेताओं के साथ चर्चा के बाद मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है और इस दौरान गठबंधन के भीतर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है। सतीशन ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं रमेश चेन्निथला, के मुरलीधरन और सनी जोसेफ को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। यूडीएफ वरिष्ठ विधायक थिरुवनचूर राधाकृष्णन को विधानसभा अध्यक्ष और शनिमोल उस्मान को उपाध्यक्ष नामित करने का फैसला किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में सतीशन के साथ विधायक रमेश चेन्निथला,पीसी विष्णुनाथ,एम लिजू,बिंदु कृष्णा,ओजे जनीश,सनी जोसेफ,रोजी एम जॉन,एपी अनिल कुमार,केए तुलसी के मुरलीधरन और टी सिद्दीकी भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सतीशन मंत्रिमंडल का बंटवारा करेंगे और इसका विस्तार भी इसी दौरान किया जा सकता है। बता दें कि विस्तार के दौरान कई अन्य विधायकों को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है।

छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री पद तक का सफर

वीडी सतीशन का जन्म वर्ष 1964 में कोच्चि के निकट नेदूर में हुआ था। पेशे से वकील रहे सतीशन ने छात्र राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और धीरे-धीरे केरल कांग्रेस की राजनीति में मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत केरल स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) से की। छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद वे यूथ कांग्रेस से जुड़े और संगठन में तेजी से उभरते नेता के रूप में पहचान बनाई। सतीशन को पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरण का करीबी और निष्ठावान समर्थक माना जाता रहा है। सतीशन का राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा रहा है। 1990 के दशक के मध्य में उन्होंने पहली बार परवूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने इस असफलता को अपनी राजनीतिक यात्रा का अंत नहीं बनने दिया और संगठन में लगातार सक्रिय रहकर अपनी मजबूत पहचान बनाई।

सीएनजी कीमतों में फिर एक रुपए की बढ़ोत्तरी..

नई दिल्ली,17 मई 2026। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपीड़ित प्राकृतिक गैस की कीमतों में तीन दिन के भीतर दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। नई दरें रविवार से लागू हो गई हैं। ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी एक रुपये प्रति किलोग्राम महंगी होकर 80.09 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले 15 मई को गैस कंपनियों ने सीएनजी की कीमतों में दो रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की थी। लगातार दूसरी बढ़ोतरी के साथ तीन दिनों में सीएनजी कुल तीन रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो चुकी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) द्वारा जारी नई दरों के अनुसार नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत बढ़कर 88.70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं,मुंबई में सीएनजी लगभग 84 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी तीन रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई थी।

राजधानी एक्सप्रेस के दो कोच में लगी आग,सभी यात्री सुरक्षित

कोटा,17 मई 2026। राजधानी एक्सप्रेस की त्रिवेंद्रम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस (12431) के दो कोचों में रविवार सुबह आग लग गई। हादसा कोटा मंडल के लूणी रीछा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच मध्य प्रदेश क्षेत्र में सुबह करीब 5.15 बजे हुआ। आग ट्रेन के बी-1 एसी कोच और उसके पीछे लगे सेकेंड लगेज कम गार्ड वैन में लगी थी। घटना की सूचना मिलते ही ट्रेन को तत्काल रोका गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, हालांकि कुछ यात्रियों का सामान आग में जल गया। पश्चिम मध्य रेलवे,कोटा मंडल के सीनियर डिवीजनल कॉमर्शियल मैनेजर सौरभ जैन ने बताया कि बी-1 कोच में 68 यात्री सवार थे। आग लगने की जानकारी सबसे पहले गार्ड ने लोको पायलट को दी, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया। लगभग 15 मिनट में पूरे कोच को खाली करा लिया गया,लेकिन कुछ ही देर में आग पूरे कोच में फैल गई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन रविवार सुबह करीब 3.45 बजे मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन से रवाना हुई थी और इसका अगला निर्धारित ठहराव कोटा जंक्शन था। राजस्थान में प्रवेश से पहले विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के निकट एसी कोच में लगी आग कुछ मिनटों में लगेज कोच तक पहुंच गई।

पीएम मोदी 8 साल बाद स्वीडन दौरे पर....
फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया,स्वीडिश प्रधानमंत्री रिसीव करने पहुंचे,बंगाली तरीके से आरती उतारी गई

एम्सटर्डम,17 मई 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल बाद स्वीडन पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने 2018 में स्वीडन का दौरा किया था। पीएम मोदी का विमान जैसे ही स्वीडन की सीमा में पहुंचा, स्वीडिश फाइटर जेट्स ने उसे सुरक्षा देते हुए एस्कॉर्ट किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन पीएम मोदी को रिसीव करने गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर पहुंचे। होटल पहुंचने पर मोदी की बंगाली तरीके से आरती उतारी गई। स्वीडन दौरे के दौरान पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। यह दौरा भारत और स्वीडन के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इस दौरान व्यापार, तकनीक, रक्षा और ग्रीन एनर्जी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों की भी उम्मीद है। इससे पहले मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्र पट्टिकाओं को भारत लाने पर समझौता हुआ। ये करीब 1000 साल पुराने तमिल दस्तावेज हैं, जिनमें चोल साम्राज्य से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी है। समझौते के तहत 11वीं सदी की चोल ताम्र पट्टिकाएं जल्द भारत लाई जाएंगी। यह 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटों का संग्रह है। इनमें ज्यादातर लेख तमिल भाषा में लिखे गए हैं। मोदी ने कहा कि इन पट्टिकाओं में राजा राजेंद्र चोल प्रथम और उनके पिता राजा राजराजा चोल प्रथम से जुड़ी जानकारी दर्ज है। ताम्र पट्टिकाएं तांबे की बनी प्लेटें होती हैं, जिन पर पुराने समय में अहम बातें लिखी जाती थीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 19वीं सदी में जब यूरोपीय देश भारत और एशिया के दूसरे हिस्सों में व्यापार और रिसर्च कर रहे थे, उसी दौरान ये दस्तावेज विदेश ले जाई गई थीं।

एलपीजी के मोर्चे पर भारत को बड़ी राहत...20 हजार टन गैस लेकर गुजरात पहुंचा जहाज 'सिमी', 13 मई को पार किया था होर्मुज

नई दिल्ली,17 मई 2026। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच 20 हजार टन एलपीजी लेकर जा रहा 'सिमी' कैरियर सुरक्षित रूप से Deendayal Port पहुंच गया है। जहाज ने 13 मई को होर्मुज स्ट्रेट पार किया था। इस जहाज पर कुल 21 क्रू सदस्य सवार हैं, जिनमें 8 यूक्रेनी और 13 फिलिपीनी नागरिक शामिल हैं। निगरानी वाले मौजूदा ऑपरेशन्स के दौरान होर्मुज स्ट्रेट पार करने वाला 'सिमी' 11वां एलपीजी टैंकर बना। अधिकारियों के अनुसार, Directorate General of Shipping, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच करीबी समन्वय के कारण जहाज की सुरक्षित आवाजाही संभव हो सकी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। इसी बीच भारत के कच्चे तेल भंडार में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ महीनों में भंडार करीब 15 प्रतिशत घट गया है। कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म Kpler के आंकड़ों के अनुसार, भारत का कुल कच्चा तेल भंडार फरवरी के अंत में 107 मिलियन बैरल था, जो अब घटकर 91 मिलियन बैरल रह गया है। इस भंडार में पेट्रोलियम रिजर्व, रिफाइनरी होल्डिंग्स और वाणिज्यिक भंडारण शामिल हैं, हालांकि पाइपलाइन स्टॉक इसमें शामिल नहीं हैं। आयात में कमी के बावजूद भारतीय रिफाइनरियों ने अब तक उत्पादन और प्रोसेसिंग का काम स्थिर बनाए रखा है। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि यदि कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा लंबे समय तक जारी रही, तो रिफाइनरियों को उत्पादन घटाने या प्रोसेसिंग स्तर कम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

फतेहपुर : रिंद नदी में स्नान करते छह युवक डूबे,चार की मौत

फतेहपुर,17 मई 2026। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में रविवार को रिन्द नदी में स्नान करते छह युवक डूब गए। इनमें से दो युवकों को स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया है, लेकिन चार युवकों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि ललौली थाना क्षेत्र के कुनुहा का डेरा गांव के समीप आज दोपहर बाद रिंद नदी में नौ युवक स्नान करने पहुंचे थे। नदी मेंनहाने के दौरान पानी के तेज बहाव के चलते छह युवक गहरे पानी में चले गए और डूब गए। मौके पर मौजूद लोगों और गोताखोरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। गोताखोरों ने दो युवक को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन चार युवकों को अचेत अवस्था में निकाला गया। पुलिस ने तुरंत ही चारों युवकों को जीवित होने की उम्मीद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिन्दकी लेकर पहुंची, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान हसीब (22) पुत्र फरीद खान, शान मोहम्मद (20) पुत्र नफीस, साहिल (20) पुत्र सन्ने और अंश कुमार (20) पुत्र धर्मेंद्र उर्फ गोरे निवासी ग्राम तपनी थाना ललौली के रूप में हुई है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नितिन और मोनू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। युवकों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में मातम छा गया।

अमित शाह का बड़ा बयान,कहा...सेवा क्षेत्र में भी नंबर वन बनेगा गुजरात,बेंगलूरू जैसे टेक हब से होगी सीधी टक्कर

अहमदाबाद,17 मई 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि मैन्युफैक्चरिंग,इंजीनियरिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब गुजरात को सेवा क्षेत्र में भी शीर्ष स्थान पर पहुंचना होगा। वह गणेश हाउसिंग के मिलियन माइंड्स टेक पार्क के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर अहमदाबाद को बेंगलूरू, हैदराबाद,पुणे और गुरुग्राम जैसे प्रमुख तकनीकी केंद्रों के समकक्ष खड़ा होना है, तो ऐसी आधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बेहद जरूरी हैं। अमित शाह ने कहा कि गुजरात ने विनिर्माण, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स,बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, हरित ऊर्जा, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और निवेश जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है।

हालांकि,अब समय आ गया है कि गुजरात को सेवा क्षेत्र में भी देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल कराया जाए। उन्होंने भरोसा जताया कि जब भी गुजरात किसी क्षेत्र में दृढ़ संकल्प के साथ कदम रखता है, तो उसे शीर्ष तीन में जगह बनाने में देर नहीं लगती।

राज्य आईटी क्षेत्र में भी यही सफलता दोहराएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन गुजरात में प्रौद्योगिकी, नवाचार,ज्ञान,उद्यमिता और उच्च कौशल आधारित उद्योगों को आकर्षित करना है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य अत्याधुनिक तकनीकों के मामले में देश का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों के डीएनए में ही उद्यमिता की भावना है। सरकार ने मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण कर इस खूबी को और बढ़ावा दिया है।

मानसून के चलते 25 मई से बंद होंगे काजीरंगा अभयारण्य के जीप सफारी

गुवाहाटी,17 मई 2026। काजीरंगा नेशनल पार्क में संचालित जीप सफारी सेवाएं 25 मई से मानसून सत्र के कारण आधिकारिक रूप से बंद कर दी जाएंगी। वन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा तथा पार्कों के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 24 मई तक जीप सफारी सामान्य रूप से संचालित होती रहेगी, जबकि 25 मई से पार्कों में पर्यटकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। मानसून के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ तथा जंगल के रास्तों की खराब स्थिति के कारण सफारी संचालन सुरक्षित नहीं माना जाता। हर वर्ष मानसून के मौसम में असम के कई राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में पर्यटन गतिविधियों को अस्थायी रूप से बंद किया जाता है, क्योंकि जलस्तर बढ़ने से जंगल के मार्ग जलमग्न हो जाते हैं और वन्यजीवों की आवाजाही भी प्रभावित होती है। वन विभाग ने बताया कि मानसून समाप्त होने के बाद परिस्थितियां सामान्य होने पर अक्टूबर या नवंबर महीने में सफारी सेवाओं को पुनः शुरू किए जाने की संभावना है।

अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु-मुंबई एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी,जल्द शुरू होगी वंदे भारत स्लीपर सेवा

नई दिल्ली,17 मई 2026। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बेंगलुरु-मुंबई एक्सप्रेस रेल सेवा को आभासी माध्यम से हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि इससे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच रेल संपर्क को मजबूती मिलेगी। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर सेवा जल्द शुरू की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक की लंबे समय से लंबित मांगों को अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में रेलवे के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे कर्नाटक में रेल परियोजनाओं के कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कर्नाटक के 61 रेलवे स्टेशनों का 2,160 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। इनमें से 9 स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है। बेंगलुरु कैंटोनमेंट स्टेशन का 485 करोड़ रुपये तथा यशवंतपुर स्टेशन का 367 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से कर्नाटक में लगभग 1,750 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं। हासन-मंगलुरु खंड में जटिल विद्युतीकरण कार्य भी पूरा कर लिया गया है और परीक्षण जारी है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना के चारों गलियारों पर कार्य चल रहा है। बैयप्पनहल्ली-चिक्कबनावरा और हीलालिगे-राजनुकुंटे गलियारों में भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है तथा स्टेशनों का निर्माण कार्य जारी है। केएसआर बेंगलुरु-देवनहल्ली मार्ग को राज्य सरकार और रेलवे की संयुक्त मंजूरी मिल चुकी है और भू-तकनीकी सर्वेक्षण पूरा हो गया है। केंगेरी-व्हाइटफील्ड मार्ग को भी हाल में स्वीकृति मिली है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्नाटक में इस समय 12 जोड़ी वंदे भारत रेलगाड़ियां संचालित हो रही हैं। बेंगलुरु-मंगलुरु मार्ग पर परीक्षण चल रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों तक संपर्क और बेहतर होगा। बेंगलुरु को हैदराबाद और चेन्नई से जोड़ने वाले बुलेट रेल गलियारों को भी मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि नई बेंगलुरु-मुंबई रेल सेवा देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक पर यात्रियों को बड़ी सुविधा देगी। थानिसंद्रा में 270 करोड़ रुपये की लागत से वंदे भारत स्लीपर अनुरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जबकि एसएमवीटी बेंगलुरु में 52.73 करोड़ रुपये की लागत से चेयर कार अनुरक्षण सुविधा विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैयप्पनहल्ली-होसुर दोहरीकरण, बेट्टहलासुरु-राजनुकुंटे परियोजना तथा बेंगलुरु क्षेत्र में चौगुनीकरण कार्यों के जरिए रेल क्षमता बढ़ाई जा रही है।

संपादकीय

प्रधानमंत्री की चेतावनी

पांच देशों के अपने दौरे के तहत संयुक्त अरब अमीरत के बाद नीदरलैंड्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए यह सही कहा कि यदि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में तेजी से सुधार नहीं होता तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीब हो जाएगी। उन्होंने यह चेतावनी देते हुए अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध और उसके चलते होर्मुज समुद्री मार्ग बाधित होने से उपजे संकट का उल्लेख किया। उनका यह कहना भी सही है कि यह दशक आपदा का दिखता है, क्योंकि पहले कोविड महामारी ने विश्व को आर्थिक संकट में धकेला,फिर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया।

इसके बाद इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव शुरू हो गया। इसके दुष्परिणामस्वरूप खाड़ी देशों से होर्मुज समुद्री मार्ग के जरिये होने वाली ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह बाधित हो गई। यह आपूर्ति अब तक बाधित है। इसके चलते पूरी दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। तेल और गैस की आपूर्ति में कमी आने के कारण लगभग सभी देशों को पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाने पड़े हैं। पिछले दिनों भारत ने भी उनके दाम बढ़ाए। इसके आसार हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल,डीजल और गैस के दाम फिर से बढ़ाने पड़ सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से समूची अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और महंगाई बढ़ती है। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीबों पर पड़ता है।

एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है,तब इससे अधिक चिंता की बात और कोई नहीं हो सकती कि उनमें से तमाम के सामने फिर से गरीब होने का संकट खड़ा हो गया है। यह खतरा केवल भारतीयों के सामने ही नहीं,अन्य विकासशील एवं निर्धन देशों के लोगों के सामने भी है। युद्धों से केवल ऊर्जा आपूर्ति ही प्रभावित नहीं होती,बल्कि सप्लाई चेन पर भी बुरा असर पड़ता है और इसके नतीजे में भी महंगाई बढ़ती है। इसमें संदेह है कि विश्व की एक बड़ी आबादी के समक्ष संकट बढ़ जाने के बाद भी शक्तिशाली देश जिम्मेदारी का परिचय देंगे और टकराव एवं तनाव कम करने के लिए सक्रिय होंगे।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय में अमेरिका ने अपनी टैरिफ नीति से तमाम देशों को तंग किया है। अब यह भी स्पष्ट है कि उसने नतीजों की परवाह किए बिना इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया। चूंकि इसका ठिकाना नहीं कि विश्व में स्थिरता और शांति कब आएगी, इसलिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार ऐसी नीतियों पर ध्यान दे,जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वास्तव में समर्थ बना सकें। कल्याणकारी नीतियां वोट के लिए नहीं,गरीब तबके को वास्तव में सबल बनाने के लिए चलाई जानी चाहिए।

ग्यारहवीं सदी की विरासत भोजशाला को मिला इक्कीसवीं सदी का न्याय

दुर्गेश्वर राय,गोरखपुर,उत्तरप्रदेश

धार की ऐतिहासिक भोजशाला का मामला, भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास,स्थापत्य कला,औपनिवेशिक काल की राजनीति और न्यायशास्त्र के अंतर्संबंधों की एक बेहद पेचीदा और जीवंत कहानी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा 15 मई 2026 को सुनाया गया ऐतिहासिक फैसला इस सदियों पुराने घटनाक्रम का एक नया और निर्णायक मोड़ है। अदालत का यह निर्णय ग्यारहवीं सदी के मालवा राजा भोज की विद्वता और ब्रिटिश काल के प्रशासनिक फैसलों की गहराइयों में उतरने का एक निमंत्रण भी है।

इस पूरे विमर्श की शुरुआत अदालत के उस फैसले से होती है जिसने वर्षों से चले आ रहे असमंजस को एक तार्किक परिणति दी। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को अपने निर्णय का मुख्य आधार बनाया। माननीय अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी ऐतिहासिक संरचना पर बाद के कालखंड में किए गए बदलावों या अतिक्रमण से उसका मूल धार्मिक चरित्र समाप्त नहीं होता। अदालत ने 07 अप्रैल 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी किए गए उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत हिंदुओं को केवल मंगलवार को पूजा और मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने माना कि किसी प्राचीन राष्ट्रीय स्मारक में इस तरह का दिनों के आधार पर विभाजन वैधानिक नहीं है। एएसआई के ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सर्वे और कार्बन डेटिंग के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि परिसर के खंभों,दीवारों और नींव में मौजूद वास्तुकला पूरी तरह सनातन परंपरा की है। इसी आधार पर हिंदू पक्ष को नियमित पूजा का अधिकार मिला जबकि मुस्लिम पक्ष को धार जिले के भीतर ही मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का विकल्प दिया गया। इसके साथ ही सरकार को लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम से माँ वाग्देवी की मूल प्रतिमा को वापस लाने के प्रयास करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया। मंदिर का स्वमित्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ही पास रहेगा जो इस फैसले को अयोध्या मामले से अलग करता है।

इस विवाद के केंद्र में जो स्थान है उसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति को समझे बिना इस निर्णय के महत्व को नहीं जाना जा सकता। मध्य प्रदेश का धार जिला जो ऐतिहासिक मालवा क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है,अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण हमेशा से रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। विंध्याचल की पहाड़ियों के साये में बसे इस क्षेत्र की मिट्टी ने भारत के कई महान राजवंशों का उत्थान और पतन देखा है। ग्यारहवीं सदी में परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया और इसे ज्ञान,कला और साहित्य के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया। राजा भोज ने यहाँ एक भव्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसे सरस्वती कंठाभरण कहा गया,और इसी नाम से संकृत व्याकरण की एक पुस्तक भी लिखी। इसी परिसर को आज हम भोजशाला के नाम से जानते हैं। यह ऐसा शैक्षणिक संस्थान था जहाँ देश-विदेश के विद्वान, कवि और दार्शनिक आकर शास्त्रार्थ करते थे। परंतु इतिहास की धारा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 13वीं और 14 वीं शताब्दी के दौरान जब मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी और बाद में दिलावर खान गोरी जैसे विदेशी आक्रांताओं के हमले हुए, तब इस सांस्कृतिक केंद्र को भारी क्षति पहुँचाई गई। इसके मूल स्वरूप को बदलकर इसे एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई,जिसके कारण उत्तर-औपनिवेशिक भारत में यह स्थान एक गंभीर विवाद का केंद्र बन गया।

भोजशाला की नींव रखने वाले राजा भोज का व्यक्तित्व अपने आप में विस्मयकारी है। वे युद्ध कौशल में निपुण होने के साथ ही एक उच्च कोटि के बहुश्रुत विद्वान,वैज्ञानिक और कवि भी थे। उनके शासनकाल को मालवा का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजा भोज की विद्वता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्वयं विभिन्न विषयों पर दर्जनों ग्रंथों की रचना की,जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में समरांगण सूत्रधार शामिल है, जो वास्तुकला और नागरिक नियोजन का एक अद्भुत और प्रामाणिक ग्रंथ है। इसके अलावा, उन्होंने सरस्वती कंठाभरण और शब्दानुशासन जैसे व्याकरण ग्रंथों की रचना की। चिकित्सा विज्ञान पर उनका ग्रंथ आयुर्वेद सर्वस्व और पतंजलि के योगसूत्र पर लिखी गई उनकी टीका राजमार्तण्ड उनकी बहुमुखी प्रतिभा के जीते-जागते प्रमाण हैं। भोजशाला की दीवारों और खंभों पर प्राकृत और संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण श्लोक,वर्णमाला के नियम और कूर्म शतक जैसे काव्य ग्रंथ आज भी चीख-चीखकर उस राजा की साहित्यिक चेतना की गवाही देते हैं, जिसने पत्थरों को भी ज्ञान का माध्यम बना दिया था। भोजशाला की पूरी कथा माँ वाग्देवी अर्थात सरस्वती की उस प्रतिमा के बिना अधूरी है,जो कभी इस परिसर के गर्भगृह की शोभा हुआ करती थी। सन 1034 ई0 में राजा भोज द्वारा स्थापित की गई यह प्रतिमा शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसके निचले हिस्से पर उत्कीर्ण शिलालेख इस संस्थान के गौरवशाली अतीत को बयाँ करता है। 1875 ई0 में भोजशाला परिसर की साफ-सफाई और खुदाई के दौरान यह ऐतिहासिक प्रतिमा सुरक्षित बाहर निकाली गई। उस समय धार रियासत में ब्रिटिश साम्राज्य का दबदबा था। सन 1902 के आसपास धार में तैनात ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर विलियम किनकेड की नजर इस अद्वितीय कलाकृति पर पड़ी। औपनिवेशिक मानसिकता के तहत वे इस बहुमूल्य धरोहर को अपने साथ ले गया। शुरुआत में इसे निजी संग्रह में रखा गया, लेकिन सन 1924 ई0 में इसे आधिकारिक तौर पर लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम को सौंप दिया गया। तब से लेकर आज तक,भारतीय वास्तुकला और अध्यात्म का यह प्रतीक विदेशी धरती पर अपनी घर वापसी की राह देख रहा है। जब माँ वाग्देवी की मूर्ति भारत से दूर जा रही थी,लगभग उसी दौर में भारत की प्राचीन विरासतों को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा तैयार हो रहा था। भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन द्वारा 18 मार्च 1904 को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक इमारतों को नष्ट होने से बचाना और उनकी अनधिकृत खुदाई या कलाकृतियों की तस्करी पर रोक लगाना था। इसी अधिनियम के तहत धार की भोजशाला को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया और इसका नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

महिलाओं के सपनों को कैद नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने विवाह,समानता और महिला स्वतंत्रता पर नई बहस को दी दिशा

डॉ. प्रियंका सौरभ
हिसार हरियाणा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी केवल एक कानूनी अवलोकन नहीं है,बल्कि भारतीय समाज की उस गहरी मानसिकता को चुनौती देने वाला ऐतिहासिक संदेश है जिसमें विवाह के बाद महिला की पहचान को अक्सर उसके पति,परिवार और घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित कर दिया जाता है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी महिला से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने करियर, महत्वाकांक्षाओं और सपनों का त्याग कर केवल आज्ञाकारी पत्नी बनकर रहे। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत की महिलाएं शिक्षा,विज्ञान, राजनीति,प्रशासन,न्यायपालिका,सेना, खेल और व्यापार जैसे हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं,लेकिन इसके बावजूद समाज का एक बड़ा वर्ग अब भी यह मानता है कि विवाह के बाद महिला की प्राथमिक जिम्मेदारी केवल घर और परिवार तक सीमित हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की पुर्नपुष्टि नहीं करती, बल्कि आधुनिक भारत में समानता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा को भी मजबूत करती है।

भारतीय समाज लंबे समय तक पितृसत्तात्मक संरचना से संचालित रहा है। इस व्यवस्था में पुरुष को परिवार का निर्णयकर्ता और आर्थिक केंद्र माना गया,जबकि महिला को त्याग, सहनशीलता और समर्पण का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया। बचपन से ही लड़कियों को यह सिखाया जाता रहा कि विवाह ही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है और विवाह के बाद उन्हें पति तथा परिवार की इच्छाओं के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। यही कारण है कि आज भी अनेक परिवारों में लड़कियों की शिक्षा को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता जितनी लड़कों की। यदि कोई महिला अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो, करियर को प्राथमिकता दे या अपने जीवन के फैसले स्वयं लेना चाहे, तो उसे कई बार परिवार विरोधी या अत्यधिक आधुनिक कहकर आलोचना का सामना करना पड़ता है। यह मानसिकता केवल महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं करती,बल्कि समाज की प्रगति को भी सीमित करती है।

विवाह के बाद महिलाओं से करियर छोड़ने या समझौता करने की अपेक्षा भारतीय समाज में सामान्य मानी जाती रही है। यदि पति की नौकरी के कारण शहर बदलना पड़े,तो पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वह बिना प्रश्न किए अपना करियर छोड़ दे। यदि परिवार और नौकरी के बीच संतुलन कठिन हो, तो त्याग की जिम्मेदारी अक्सर महिला पर ही डाली जाती है। मातृत्व के बाद महिलाओं पर घरेलू जिम्मेदारियों का इतना अधिक बोझ डाल दिया जाता है कि लाखों महिलाएं अपनी योग्यता और प्रतिभा के बावजूद नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत स्तर पर अन्याय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास के लिए भी नुकसानदायक है। एक ऐसा देश जो अपनी आधी आबादी की प्रतिभा का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता,वह कभी भी अपनी संपूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच सकता।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भारतीय संविधान की मूल भावना को भी मजबूत करती है। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। किसी महिला से यह अपेक्षा करना कि वह केवल इसलिए अपने सपनों और करियर का त्याग कर दे क्योंकि वह विवाहित है, इन संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि विवाह किसी महिला की स्वतंत्र पहचान समाप्त करने का माध्यम नहीं हो सकता। पत्नी कोई अधीनस्थ व्यक्ति नहीं, बल्कि समान अधिकारों वाली स्वतंत्र नागरिक है।

आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। अंतरिक्ष से लेकर युद्धक विमान तक, न्यायपालिका से लेकर स्टार्टअप जगत तक, महिलाएं अपनी क्षमता का परिचय दे रही हैं। पीवी सिंधु,मीराबाई चानू,साइना नेहवाल,फाल्गुनी नायर, निर्मला सीतारमण,गीता गोपीनाथ और अनेक अन्य महिलाओं ने यह सिद्ध किया है कि अवसर मिलने पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इन उपलब्धियों के बावजूद समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर पारंपरिक सोच पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आज भी अनेक शिक्षित परिवारों में यह माना जाता है कि पत्नी की सफलता पति से अधिक नहीं होनी चाहिए। कई बार महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को पुरुष अहंकार के लिए चुनौती के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि कार्यस्थलों पर लैंगिक भेदभाव,वेतन असमानता और मानसिक दबाव जैसी समस्याएं अब भी मौजूद हैं।

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, तब वे अपने निर्णय अधिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ ले पाती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और असमान व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति भी देती है। इसलिए करियर केवल आय अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। यदि किसी महिला को विवाह के नाम पर अपने करियर का त्याग करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वास्तव में उसकी स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसी सोच को अस्वीकार करती है और यह स्पष्ट करती है कि महिला का करियर कोई शौक नहीं, बल्कि उसका संवैधानिक और मानवीय अधिकार है। हालांकि केवल न्यायिक टिप्पणियां समाज में पूर्ण परिवर्तन नहीं ला सकतीं।

वास्तविक बदलाव तब आएगा जब परिवारों की सोच बदलेगी। आज भी घरों में घरेलू कार्यों और बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर डाल दी जाती है। पुरुषों की घरेलू भागीदारी सीमित रहती है,जबकि कामकाजी महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे नौकरी के साथ-साथ घर की हर जिम्मेदारी भी निभाएं। यही दोहरा बोझ महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि पति-पत्नी घरेलू जिम्मेदारियों को समान रूप से साझा करें, तो महिलाएं बिना अपराधबोध के अपने करियर और सपनों को आगे बढ़ा सकती हैं। आधुनिक विवाह का आधार समानता, सहयोग और पारस्परिक सम्मान होना चाहिए,न कि नियंत्रण और अधीनता। समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता का विरोध अक्सर संस्कृति और परंपरा के नाम पर किया जाता है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि कोई भी संस्कृति तभी जीवंत और प्रगतिशील मानी जाती है जब वह अपने नागरिकों को समान अवसर और सम्मान प्रदान करे। यदि परंपराओं के नाम पर महिलाओं को दबाया जाए,उनके सपनों को सीमित किया जाए और उनकी स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखा जाए, तो वह संस्कृति नहीं बल्कि असमानता की व्यवस्था बन जाती है। भारतीय सभ्यता में नारी शक्ति को हमेशा सम्मान दिया गया है। देवी सरस्वती को ज्ञान, लक्ष्मी को समृद्धि और दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना गया। लेकिन वास्तविक जीवन में महिलाओं को समान अवसर देने में समाज अक्सर पीछे रह जाता है। यही विरोधाभास आज भी भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

नई पीढ़ी की महिलाएं अब अपने अधिकारों और सपनों को लेकर अधिक जागरूक हैं। वे विवाह को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती हैं, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। वे ऐसे रिश्ते चाहती हैं जहां सम्मान, स्वतंत्रता और सहयोग हो। डिजिटल युग और शिक्षा के विस्तार ने महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाया है। सोशल मीडिया और वैश्विक संपर्क ने उन्हें यह समझने का अवसर दिया है कि दुनिया तेजी से बदल रही है और महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन दूसरी ओर समाज का एक हिस्सा अब भी पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पाया है। यही कारण है कि महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर कई बार सामाजिक तनाव और संघर्ष देखने को मिलते हैं। ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय की प्रगतिशील टिप्पणियां समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करती हैं।

भारत में महिला श्रम भागीदारी दर अब भी अपेक्षाकृत कम है। बड़ी संख्या में महिलाएं विवाह और मातृत्व के बाद कार्यक्षेत्र छोड़ देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है, जहां सामाजिक रूढ़ियां और आर्थिक सीमाएं महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। यदि भारत को वास्तव में वैश्विक शक्ति बनना है,तो उसे महिलाओं की प्रतिभा और क्षमता का पूरा उपयोग करना होगा। विश्व बैंक और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें बताती हैं कि यदि महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़े,तो भारत की अर्थव्यवस्था को भारी लाभ हो सकता है। इसलिए महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के अवसर देना केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि आर्थिक विकास की आवश्यकता भी है।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी पुरुषों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। महिलाओं की स्वतंत्रता पुरुषों के अधिकारों के खिलाफ नहीं है। समानता का अर्थ प्रतिस्पर्धा नहीं,बल्कि साझेदारी है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो परिवार,समाज और राष्ट्र सभी मजबूत होते हैं। एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महिला बेहतर निर्णय ले सकती है, बच्चों को बेहतर शिक्षा और संस्कार दे सकती है तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इसलिए महिलाओं की सफलता को चुनौती नहीं, बल्कि सामूहिक प्रगति के रूप में देखा जाना चाहिए।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि मानसिक स्वतंत्रता के बिना कानूनी अधिकार अधूरे रह जाते हैं। यदि समाज महिलाओं को लगातार अपराधबोध, सामाजिक दबाव और पारिवारिक अपेक्षाओं के बोझ तले दबाए रखेगा,तो वे पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने निर्णय नहीं ले पाएंगी। इसलिए आवश्यकता केवल कानून बदलने की नहीं,बल्कि मानसिकता बदलने की भी है। स्कूलों, परिवारों और सामाजिक संस्थाओं को बचपन से ही लड़के और लड़कियों दोनों को समानता और सम्मान का मूल्य सिखाना होगा। पुरुषों को यह समझना होगा कि घरेलू कार्य केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं हैं। महिलाओं को भी यह विश्वास दिलाना होगा कि उनके सपने और महत्वा कांक्षाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी किसी पुरुष की।

अंततः सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी आधुनिक भारत के लिए एक नैतिक दिशा-निर्देश की तरह है। यह केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात नहीं करती,बल्कि उस समाज की कल्पना प्रस्तुत करती है जहां विवाह समानता और सम्मान का संबंध हो, जहां महिलाओं को अपने सपनों के लिए अपराधबोध महसूस न करना पड़े और जहां किसी भी महिला को अच्छी पत्नी साबित करने के लिए अपनी पहचान का बलिदान न देना पड़े। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। यदि भारत को वास्तव में विकसित,आधुनिक और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनना है, तो उसे अपनी महिलाओं को केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि अवसर, सम्मान और स्वतंत्रता भी देनी होगी। महिलाओं के सपनों को कैद करके कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जब भारत की महिलाएं बिना भय, दबाव और भेदभाव के अपने सपनों को जी सकेंगी, तभी सच्चे अर्थों में संविधान में निहित समानता और स्वतंत्रता के आदर्श साकार हो पाएंगे।

वह माँ जो बँटे बच्चों को फिर से गोद में ले रही है...

कृति आरके जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

संग्रहालय : जहाँ हर कलाकृति कहती है हम सब एक हैं...

संग्रहालय : जहाँ हर कलाकृति एक टूटा हुआ रिश्ता जोड़ती है...

बिखरती मानवीय संवेदनाओं और बढ़ती दूरियों के बीच संग्रहालय साझा संस्कृति और इतिहास की सबसे सशक्त आवाज बनकर उभरे हैं। प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक चेतना के महत्व को रेखांकित करता है। वर्ष 2026 की विषय-वस्तु संग्रहालय विभाजित विश्व को एकजुट करते हैं आज की सबसे बड़ी आवश्यकता को व्यक्त करती है। युद्ध, सांप्रदायिकता, सांस्कृतिक संघर्ष,आर्थिक असमानता और सामाजिक तनाव से घिरी दुनिया में संग्रहालय ऐसे शांतिपूर्ण केंद्र बन गए हैं,जहाँ विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के लोग एक-दूसरे को समझते हैं। वे यह संदेश देते हैं कि विविधता मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है।

समय बदलता है,पर सभ्यता की पहचान संग्रहालयों में सुरक्षित रहती है। मानव इतिहास,संस्कृति और विरासत के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने वर्ष 1977 में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुरुआत की। आज विश्व के लगभग 95000 संग्रहालय इस संगठन से जुड़े हैं तथा 37000 से अधिक संग्रहालय प्रदर्शनी, संगोष्ठी और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से इसे मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी संग्रहालयों को शांति, सामाजिक समानता और सांस्कृतिक सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम माना है। संग्रहालय केवल प्राचीन वस्तुओं के संग्रह नहीं,बल्कि इतिहास और समाज को जोड़ने वाले जीवंत ज्ञान-केंद्र हैं। वैज्ञानिक प्रगति और आधुनिक तकनीक के शिखर पर पहुँचा विश्व आज भी सामाजिक विभाजन, युद्ध और कट्टरता की आग में घिरा दिखाई देता है। नस्लीय भेदभाव,धार्मिक उन्माद और राजनीतिक संघर्षों ने मानवता को गहरे संकट में डाल दिया है,जिससे करोड़ों लोग हिंसा और विस्थापन का जीवन जीने को विवश हैं। ऐसे समय में संग्रहालय मानवता के बीच संवाद,समझ और सहअस्तित्व के सशक्त माध्यम बनकर उभरते हैं। किसी अन्य देश या समुदाय की कला,परंपरा और जीवन शैली को निकट से देखकर लोगों के मन में सम्मान और संवेदनशीलता विकसित होती है। संग्रहालय यह संदेश देते हैं कि प्रत्येक संस्कृति मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर है तथा भिन्नताओं के बावजूद मानवता की मूल भावनाएँ सर्वत्र समान हैं। विश्व के महान संग्रहालय मानव सभ्यता की साझा विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। फ्रांस का लौवर संग्रहालय विश्व का सर्वाधिक देखा जाने वाला संग्रहालय है,जहाँ प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख से अधिक पर्यटक पहुँचते हैं। ब्रिटेन का ब्रिटिश संग्रहालय,अमेरिका का मेट्रो पोलिटन संग्रहालय तथा रूस का हर्मिटेज संग्रहालय जैसे संग्रहालय विभिन्न सभ्यताओं की अमूल्य धरोहरों को संजोए हुए हैं। यहाँ मिस्र की ममियाँ,भारतीय मूर्तियाँ,यूनानी प्रतिमाएँ,चीनी चित्रकला और अफ्रीकी कलाकृतियाँ एक साथ दिखाई देती हैं। इन्हें देखकर अनुभव होता है कि मानव सभ्यता का निर्माण संघर्ष से नहीं,बल्कि संस्कृति, सहयोग और आदान-प्रदान से हुआ है। संग्रहालय सीमाओं से ऊपर उठकर विश्वबंधुत्व और मानव एकता का संदेश देते हैं। सभ्यताओं की स्मृतियों को संजोए संग्रहालय भारत की सांस्कृतिक चेतना के जीवंत प्रतीक हैं। नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय,कोलकाता का भारतीय संग्रहालय,मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय और भोपाल का जनजातीय संग्रहालय भारत की बहुरंगी संस्कृति को सजीव रूप देते हैं। इन संग्रहालयों में सिंधु घाटी सभ्यता की धरोहरें,बौद्ध कला, मुगल चित्रकला, स्वतंत्रता संग्राम और जनजातीय जीवन की अनमोल झलक सुरक्षित है। देशभर में एक हजार से अधिक संग्रहालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर नई पीढ़ी को इतिहास,परंपरा और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ रहे हैं। यही धरोहर भारत की विविधता में एकता की वास्तविक पहचान है। डिजिटल युग ने संग्रहालयों की पहचान बदल दी है। अब इतिहास और संस्कृति केवल भवनों तक सीमित नहीं,बल्कि इंटरनेट के माध्यम से विश्वभर तक पहुँच रहे हैं। वर्चुअल भ्रमण, संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता जैसी तकनीकों ने संग्रहालयों को अधिक जीवंत और ज्ञानवर्धक बना दिया है। कोविड महामारी के दौरान लाखों विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं ने घर बैठे विश्वप्रसिद्ध संग्रहालयों का अवलोकन किया। आज ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी भी वैश्विक सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकें आगंतुकों को रुचि अनुसार जानकारी देकर संग्रहालयों को आधुनिक ज्ञान-केंद्र बना रही हैं।

संग्रहालय आज समाज में जागरूकता और सहभागिता के प्रभावशाली केंद्र बन चुके हैं। वे पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण,आदिवासी अधिकार, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक पहचान जैसे विषयों पर जनचेतना फैला रहे हैं। लोककला प्रदर्शन,कार्यशालाएँ और कहानी-कथन कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों को संवाद का अवसर देते हैं। संग्रहालय सहिष्णुता,सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हुए यह संदेश देते हैं कि राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक विकास नहीं,बल्कि सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्यों पर भी आधारित होती है।

इतिहास और संस्कृति के प्रहरी संग्रहालय आज अनेक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आर्थिक संसाधनों की कमी, आधुनिक तकनीकों का अभाव और प्रशिक्षित कर्मचारियों की न्यूनता उनकी प्रगति में बाधा बन रही है। डिजिटल मनोरंजन के बढ़ते प्रभाव से युवाओं का रुझान भी इनसे दूर हो रहा है। साथ ही युद्ध, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाएँ सांस्कृतिक धरोहरों को निरंतर क्षति पहुँचा रही हैं। फिर भी अनेक संग्रहालय नई तकनीकों,शैक्षिक गतिविधियों और जनसहभागिता के माध्यम से स्वयं को अधिक प्रभावी बना रहे हैं। सरकार, समाज और शिक्षण संस्थाओं के संयुक्त प्रयास उन्हें भविष्य के सशक्त सांस्कृतिक केंद्र बना सकते हैं।

युगों की विरासत को संजोए संग्रहालय मानव सभ्यता की स्मृति और संस्कृति के अमर संरक्षक हैं। वे अतीत की धरोहरों को सुरक्षित रखकर वर्तमान को जागरूक और भविष्य को प्रेरित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यह स्मरण कराता है कि संस्कृति और इतिहास समाज को जोड़ने की सबसे बड़ी शक्ति हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह संग्रहालयों के संरक्षण में सहयोग दे और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़े। जब विभिन्न संस्कृतियों के प्रति समझ और सम्मान बढ़ेगा, तभी विश्व में शांति,सहिष्णुता और भाईचारा सुदृढ़ होगा। संग्रहालय वास्तव में मानवता को जोड़ने वाले सशक्त सांस्कृतिक सेतु हैं।

संग चलें भोले

कार्तिकेय कुमार त्रिपाठी राम
इन्दौर,मध्यप्रदेश

संग चल रहे भोले मेरे,
मन का साज बजाते हैं,
दुनियादारी छोड़ के सारी,
मंद-मंद मुस्काते हैं।
संग चल रहे भोले ...
जहां-जहां हों प्रेम की बाते,
भोले वहां आ जाते हैं,
तान छेड़ डमरू की भोले,
सबको नाच-नचाते हैं।
संग चल रहे भोले ...
मिट्टी के कण-कण में भोले,
छवि सदा दिखलाते हैं,
जहां मैं पूजा करता उनको,
वहीं नजर आ जाते हैं।
संग चल रहे भोले ...
आसमान में तारे जितने,
भेद छुपे भोले में उतने,
जहां पुकारो भक्ति-भाव से,
वहीं उतर कर आते हैं।
संग चल रहे भोले ...
भोले तो हैं प्रेम के प्यासे,
इत-उत आते-जाते हैं,
जहां भक्ति की गंगा बहती,
खुद भोले मुस्काते हैं।
संग चल रहे भोले ....

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

पेट्रोल-डीजल संकट और महंगाई के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर

अम्बिका पेट्रोल पंप में धरना,केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को बताया 'जनविरोधी'

'तेल कंपनियां कमा रहीं मुनाफा,जनता भुगत रही महंगाई की मार' : बालकृष्ण पाठक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 मई 2026
(घटती-घटना)।

पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों, कई क्षेत्रों में ईंधन की अनियमित आपूर्ति, बढ़ती महंगाई और विवाह सीजन के बीच सोने की खरीददारी को लेकर प्रधानमंत्री की अपील के विरोध में रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने जिला मुख्यालय अंबिकापुर सहित विभिन्न ब्लॉकों में धरना-प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौक स्थित अम्बिका पेट्रोल पंप में आयोजित मुख्य प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आम जनता को महंगाई से राहत देने की मांग उठाई। यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा घोषित चार दिवसीय आंदोलन का हिस्सा है। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला और ब्लॉक स्तर पर अलग-अलग स्थानों में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस ने 17 मई को पेट्रोल पंप, 18 मई को किराना दुकानों और 19 मई को सराफा दुकानों के सामने धरना-प्रदर्शन एवं जनसंवाद कार्यक्रम तय किया है। वहीं 20 मई को सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर अभियान चलाया जाएगा।

'जनता परेशान,कंपनियां मुनाफे में : धरना प्रदर्शन के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत बनी हुई है, जबकि बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के करीबी उद्योगपतियों की कंपनियां देश में उपलब्ध कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों में निर्यात कर रही हैं, जबकि देश की जनता महंगे पेट्रोल-डीजल और महंगाई का बोझ उठा रही है। उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बेहद कम थीं, तब भी जनता को राहत नहीं दी गई और तेल कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया। बालकृष्ण पाठक ने दावा किया कि पेट्रोलियम कंपनियों और सरकार ने बीते वर्षों में लाखों करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचा। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का पूरा बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है।

किराना और सराफा बाजारों में भी होगा आंदोलन : कांग्रेस ने साफ किया है कि आंदोलन केवल पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहेगा। 18 मई को किराना दुकानों के सामने महंगाई के विरोध में धरना-प्रदर्शन कर व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया जाएगा। वहीं 19 मई को सराफा बाजारों में प्रदर्शन कर सोने-चांदी के कारोबार पर पड़े असर को लेकर विरोध जताया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के कारण बाजार प्रभावित हो रहे हैं। विवाह सीजन में भी खरीददारी कमजोर पड़ रही है, जिससे छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है।

बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता : धरना प्रदर्शन में मो. इस्लाम, अरविंद सिंह, विनय शर्मा, इंद्रजीत सिंह धंजल, दुर्गेश गुप्ता, आलोक सिंह, जीवन यादव, लोकेश कुमार, गुरूप्रीत सिद्धू, चंद्रप्रकाश सिंह, रजनीश सिंह, सोहन जायसवाल, नीतीश चौरसिया, अविनाश कुमार, अमित सिंह, हिमांशु जायसवाल, आशीष जायसवाल, लुकस एक्का, अंकित जायसवाल, ऋषभ जायसवाल, जयवंत मिंज सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने महंगाई और ईंधन संकट को लेकर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

पेट्रोल पंप संचालकों ने भी जताई चिंता

धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप संचालकों एवं उपभोक्ताओं से बातचीत कर वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पहले की तुलना में प्रभावित हो रही है। कई कंपनियों से नियमित सप्लाई नहीं मिलने के कारण कई पेट्रोल पंप 'ड्राई' होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे केंद्र सरकार की विफल आर्थिक नीति का परिणाम बताते हुए कहा कि ईंधन संकट का सीधा असर परिवहन, कृषि, व्यापार और आम लोगों की दैनिक जरूरतों पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों ने मध्यम और निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति को और कठिन बना दिया है।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

लखनपुर में पेट्रोल पंप के सामने धरना,केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी

लखनपुर,17 मई 2026(घटती-घटना)। पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लखनपुर द्वारा जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के निर्देश पर आयोजित यह प्रदर्शन नारायण पेट्रोल पंप, लखनपुर में किया गया। धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सिंह देव ने किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पेट्रोल-डीजल के बढ़े हुए दाम वापस लेने और आम जनता को महंगाई से राहत देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल और डीजल महंगे होने से परिवहन, कृषि, व्यापार और रोजमर्रा की जरूरतों पर सीधा असर पड़ रहा है। महंगाई के कारण आम जनता का जीवन कठिन होता जा रहा है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष रमेश जायसवाल, दिनेश तायल, जमील खान, जगरोपण यादव, मुकेश सिंह, जिला सचिव इरशाद खान, ब्लॉक उपाध्यक्ष सतेंद्र राय, असफाक खान, महामंत्री रामसूजान द्विवेदी, मकसूद खान, स्वपनिल शर्मा, किसान कांग्रेस अध्यक्ष अजर चौधरी, गप्पू खान, ब्लॉक सचिव मोजीब खान, अमरेश राजवाड़े, भूपेंद्र जायसवाल, इमरान खान, ताहिर नूर, रिंकू, भुनेश्वर यादव, अनिल गुप्ता, जसीमुद्दीन खान, नवीन पाण्डेय और रामप्रकाश राजवाड़े सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने जल्द ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत नहीं दी, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

गर्भवती पत्नी की हत्या कर फरार हुआ पति गिरफ्तार

महिला के शरीर पर मिले 16 गंभीर चोट के निशान,प्राइवेट पार्ट में मिला लोहे का रेती...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 मई 2026
(घटती-घटना)।

मणिपुर थाना क्षेत्र के भिट्ठीकला गांव में तीन माह की गर्भवती पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी वारदात के बाद तीन दिन से फरार था और बांकी डेम के पास जंगल में छिपा हुआ था। जानकारी के अनुसार भिट्ठीकला निवासी हीरो बाई अगरिया (23) की 14 मई को उसके पति प्रदीप अगरिया ने हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में घर पहुंचा था। किसी मामूली बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद प्रदीप ने गुस्से में आकर लकड़ी से पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के समय उनके तीन छोटे बच्चे भी घर में मौजूद थे। गंभीर रूप से घायल होने पर आरोपी पत्नी को गमछे से बांधकर बाइक से मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पत्नी की मौत की जानकारी मिलते ही आरोपी शव को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया था।

पोस्टमार्टम में सामने आई क्रूरता : अगले दिन फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉ. संतू बाघ की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। जांच के दौरान महिला के प्राइवेट पार्ट में करीब 10 इंच का लोहे का रेती मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर 16 गंभीर चोट के निशान पाए गए। अत्यधिक क्रूरता के कारण उसका गर्भाशय भी फट गया था।

जंगल में छिपा था आरोपी : मृतका के भाई प्रसन्न अगरिया की रिपोर्ट पर मणिपुर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। तीसरे दिन पुलिस ने बांकी डेम के पास जंगल में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने गुस्से में हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

ऊर्जा संकट और साइकिल संस्कृति पर डॉ. योगेंद्र सिंह गहरवार की पहल....

'सिर्फ अपील नहीं,सुरक्षित साइकिल ट्रैक और बेहतर शहरी संरचना की जरूरत'

सुजान बिंद की साइकिल यात्रा पर घर की चर्चा से निकला आत्मनिर्भर भारत का संदेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 मई 2026
(घटती-घटना)।

ऊर्जा संकट, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली को लेकर डॉ. योगेंद्र सिंह गहरवार द्वारा लिखे गए विचार इन दिनों चर्चा में हैं। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सुजान बिंद की साइकिल यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी पहल को व्यक्ति विशेष की राजनीतिक पहचान से नहीं,बल्कि उसके समाज और राष्ट्रहित से जोड़कर देखा जाना चाहिए। डॉ. गहरवार ने लिखा कि सुजान बिंद 'मोदी भक्त' नहीं बल्कि 'राष्ट्र भक्त' हैं और उनकी सोच समाजहित से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि असली प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है या कब कह रहा है, बल्कि यह होना चाहिए कि उस विचार से देश, समाज और आने वाली पीढ़ियों का भला होगा या नहीं।

'अच्छे विचारों को स्वीकार करना ही परिपक्व समाज की पहचान : उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की पहल से ऊर्जा बचत,पर्यावरण संरक्षण, बेहतर स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है, तो उसे केवल वैचारिक मतभेद के कारण खारिज नहीं किया जाना चाहिए। डॉ. गहरवार के अनुसार राष्ट्र निर्माण व्यक्तियों के अहंकार से नहीं बल्कि अच्छे विचारों को स्वीकार करने की सामूहिक क्षमता से होता है।

होर्मुज संकट के बीच ऊर्जा बचत पर जोर : उन्होंने वैश्विक ऊर्जा संकट और होर्मुज खाड़ी जैसी परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अभी भी पेट्रोलियम उत्पादों के लिए बड़े स्तर पर आयात पर निर्भर है। ऐसे में केवल लोगों से पेट्रोल-डीजल कम उपयोग करने की अपील पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि ऐसी शहरी संरचना विकसित करनी होगी जिससे लोग स्वाभाविक रूप से साइकिल और पैदल चलने को अपनाएं।

अंबिकापुर में डेडिकेटेड साइकिल कॉरिडोर की मांग : डॉ. गहरवार ने अंबिकापुर शहर में डेडिकेटेड साइकिल कॉरिडोर विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर कॉलेज से महामाया मंदिर तक तथा उत्तर-दक्षिण बिलासपुर चौक से प्रतापपुर तक सुरक्षित साइकिल ट्रैक बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा बनारस चौक से गांधीनगर और रिंग रोड तक वॉकिंग एवं साइकिलिंग ट्रैक विकसित करने की भी आवश्यकता बताई गई।

सिर्फ फ्लाईओवर नहीं,सुरक्षित पैदल और साइकिल संस्कृति भी विकास

उन्होंने कहा कि किसी शहर का विकास केवल चौड़ी सड़कें और फ्लाईओवर बनने से नहीं मापा जाना चाहिए। वास्तविक विकास तब माना जाएगा जब नागरिक बिना भय के पैदल चल सकें और सुरक्षित रूप से साइकिल चला सकें। उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था बनने से लोग छोटी दूरियों के लिए मोटर वाहनों पर निर्भरता कम करेंगे, जिससे ईंधन की बचत होगी और पर्यावरण भी बेहतर होगा।

स्वास्थ्य लाभ भी होंगे...

डॉ. गहरवार ने कहा कि साइकिल और वॉकिंग संस्कृति बढ़ने से मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज जो कदम ऊर्जा संकट के कारण जरूरी लग रहे हैं, वही भविष्य में स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन सकते हैं।

अपहृत नाबालिग बालिका रायपुर से बरामद.. मणिपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल,परिजनों ने ली राहत की सांस

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 मई 2026
(घटती-घटना)।

मणिपुर थाना पुलिस ने अपहृत नाबालिग बालिका को रायपुर से बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बालिका के सकुशल मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी ने थाना मणिपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी 17 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 2.30 बजे बिलासपुर चौक जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश की,लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। रिपोर्ट पर मणिपुर थाना में धारा 137(2), 64(2) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस टीम लगातार बालिका की तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी विजय पोर्ते रायपुर जिले के बिरगांव स्थित किसान राइस मिल के पास मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश दी और आरोपी के कब्जे से नाबालिग बालिका को बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपी विजय पोर्ते (24) निवासी पटोरा खालपारा थाना लुंड्रा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद 17 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका : पूरे मामले की कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक सी.पी. तिवारी, सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डेय, महिला प्रधान आरक्षक मालती तिवारी, आरक्षक अनील सिंह, उमाशंकर साहू और रमाशंकर यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

गांधी स्टेडियम में क्रिकेट पर घमासान! 'बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता'...खिलाड़ियों और परिजनों का फूटा गुस्सा....

क्रिकेट संघ सचिव पर मनमानी के आरोप,मैच रद्द होने से भड़का विवाद...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 मई 2026
(घटती-घटना)।

गांधी स्टेडियम में क्रिकेट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जूनियर खिलाड़ियों और उनके परिजनों ने सरगुजा क्रिकेट संघ के सचिव विनीत विशाल जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि मैदान में बच्चों को खेलने नहीं दिया जा रहा,मैच रद्द कर दिए जाते हैं और क्रिकेट गतिविधियों पर कुछ लोगों का एकाधिकार बना हुआ है। विवाद उस समय और बढ़ गया जब अंडर-14 खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के लिए बुलाए जाने के बाद मैदान पहुंचने पर मैच रद्द होने की जानकारी मिली। परिजनों का आरोप है कि बच्चों को पहले बुलाया गया, लेकिन बाद में खेलने से रोक दिया गया।

'मैदान पहुंचते ही कहा गया — मैच नहीं होगा : क्रिकेट खिलाड़ी आशुतोष प्रजापति ने आरोप लगाया कि सुबह खिलाड़ी मैच खेलने गांधी स्टेडियम पहुंचे थे। कुछ देर बाद क्रिकेट संघ के सचिव पहुंचे और साफ शब्दों में कह दिया कि यहां कोई मैच नहीं होगा। खिलाड़ी का आरोप है कि मैदान में बच्चों को नियमित अभ्यास तक नहीं करने दिया जाता। स्टंप उपलब्ध नहीं कराए जाते, कई बार ग्राउंड में ताला लगा दिया जाता है और हर गतिविधि के लिए अनुमति लेने की स्थिति बना दी गई है। आशुतोष ने सवाल उठाते हुए कहा, 'जब यह नगर निगम की संपत्ति है तो किसी एक संस्था का पूर्ण अधिकार कैसे हो सकता है?'

बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ : अंडर-14 खिलाड़ी के अभिभावक पीयूष त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि खिलाड़ियों और परिजनों को पहले से मैच रद्द होने की कोई सूचना नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बच्चे सुबह से तैयारी कर मैदान पहुंचे थे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि मैच नहीं होगा। परिजनों का कहना है कि लगातार ऐसे हालात बनने से बच्चों का मनोबल टूट रहा है और सरगुजा की क्रिकेट प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। पीयूष त्रिपाठी ने नाराजगी जताते हुए कहा, 'क्रिकेट धूप, मिट्टी और पसीने का खेल है। अगर एसी में बैठकर क्रिकेट खेलना होता तो यह इंडोर गेम होता। बच्चे अपनी इच्छा और माता-पिता की सहमति से खेलने आते हैं, फिर उन्हें रोकना गलत है।' उन्होंने आरोप लगाया कि रायपुर और भिलाई जैसे शहरों के खिलाड़ियों को ज्यादा अवसर मिलते हैं, जबकि सरगुजा के बच्चों को पर्याप्त मैच और एक्सपोजर नहीं दिया जाता।

अकादमियों की लड़ाई में पिस रहे खिलाड़ी : स्थानीय अभिभावकों ने आरोप लगाया कि शहर में कई क्रिकेट अकादमियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और इसका सीधा नुकसान खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि व्यक्तिगत खींचतान और नियंत्रण की राजनीति के कारण बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

सचिव ने कहा — '20 टूर्नामेंट करा चुके हैं : आरोपों पर जवाब देते हुए विनीत विशाल जायसवाल ने सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में 20 से अधिक लेदर बॉल टूर्नामेंट आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें जिला, संभाग और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। सचिव का कहना है कि मैदान अब सार्वजनिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। यहां टेनिस बॉल टूर्नामेंट और अन्य आयोजन होने लगे हैं, जिससे मैदान की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और राज्य स्तरीय मैच मिलने में दिक्कत आ रही है।

सरगुजा के खिलाड़ी रणजी तक पहुंचे...

सचिव ने यह भी दावा किया कि सरगुजा क्रिकेट संघ का प्रदर्शन बेहतर रहा है और यहां के खिलाड़ी उच्च स्तर तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि रणजी ट्रॉफी तक क्षेत्र के खिलाड़ी पहुंचे हैं और उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से संघ लगातार काम कर रहा है।

अब सवालों के घेरे में पूरी खेल व्यवस्था

पूरा विवाद अब केवल एक मैच रद्द होने का मामला नहीं रह गया है। खिलाड़ियों और परिजनों का कहना है कि यदि जिला स्तर पर ही बच्चों को खेलने का अवसर नहीं मिलेगा तो क्षेत्र की प्रतिभाएं आगे कैसे बढ़ेंगी। स्थानीय खेल प्रेमियों का कहना है कि जिला प्रशासन,नगर निगम और क्रिकेट संघ को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, ताकि गांधी स्टेडियम जैसे सार्वजनिक मैदानों का उपयोग पारदर्शी तरीके से हो सके और खिलाड़ियों को बिना विवाद नियमित अभ्यास व मैच का अवसर मिल सके।

CMYK

आजादी के बाद पहली बार रोशनी से जगमगाएगा वनांचल

गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के गांवों तक पहुंचेगी नियमित बिजली,14.88 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी

टाइगर रिजर्व क्षेत्र का सांख्यिकीय ढांचा (एक नजर में)

ग्राम पंचायत	गांवों की संख्या	कुल जनसंख्या	कुल मकान
आनंदपुर	3	1404	650
दसेर	2	466	94
नटवाही	4	1606	439
सिंघोर	3	1596	346
उज्ञावं	3	846	198
अमृतपुर	3	808	178
रामगढ़	4	1996	400
कुल योग	21	8722	2005

-राजन पाण्डेय-

बैकुंठपुर/सोनहत 17 मई 2026 (घटती-घटना)।

गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच बसे हजारों ग्रामीणों के लिए एक ऐतिहासिक और लंबे इंतजार के बाद राहत देने वाली खबर सामने आई है, आजादी के बाद दशकों तक अंधेरे में जीवन गुजारने को मजबूर वनांचल क्षेत्र अब पहली बार नियमित बिजली की रोशनी से जगमगाने जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस महत्वाकांक्षी विद्युत परियोजना के लिए 14.88 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है, इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जंगलों के बीच से लगभग 87 किलोमीटर लंबी हाईटेंशन लाइन बिछाकर दूरस्थ गांवों तक बिजली पहुंचाई जाएगी, इस परियोजना से 7 ग्राम पंचायतों के लगभग 2005 घरों में रहने वाली करीब 8722 आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। वर्षों से बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित लोगों के लिए यह योजना केवल एक सरकारी परियोजना नहीं, बल्कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की नई उम्मीद बनकर सामने आई है।

दशकों से अंधेरे में जी रहा था वनांचल

कोरिया जिले के वनांचल ब्लॉक सोनहत का रामगढ़ क्षेत्र लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा था। यह पूरा इलाका घने जंगलों और टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण यहां सामान्य विकास कार्यों को लागू करना बेहद कठिन माना जाता रहा है, आजादी के बाद भी यहां के कई गांव नियमित बिजली व्यवस्था से वंचित रहे,ग्रामीणों का जीवन लालटेन, ढिबरी और सीमित सोलर लाइट के भरोसे चलता था। रात होते ही पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता था, गांवों में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामान्य जीवन व्यवस्था बिजली की कमी से लगातार प्रभावित होती रही।

राष्ट्रीय उद्यान और जंगल बना बड़ी बाधा-

रामगढ़ और आसपास का यह क्षेत्र पहले राष्ट्रीय उद्यान घोषित था और वर्तमान में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, वन संरक्षण से जुड़े कड़े नियमों और पर्यावरणीय अनुमति की जटिल प्रक्रिया के कारण यहां बिजली लाइन पहुंचाना लंबे समय तक संभव नहीं हो पाया, विकासखंड मुख्यालय सोनहत से रामगढ़ तक लगभग 35 किलोमीटर का घनघोर जंगल पड़ता है। इस कठिन भौगोलिक क्षेत्र में बिजली लाइन विस्तार तकनीकी और प्रशासनिक दोनों स्तर पर चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था, इसी वजह से वर्षों तक ग्रामीण नियमित बिजली सुविधा से वंचित रहे।

सोलर व्यवस्था भी नहीं बन सकी स्थायी समाधान-

ग्रामीणों को अस्थायी राहत देने के लिए पहले सोलर सिस्टम उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन वह भी स्थायी समाधान साबित नहीं हो सके, स्थानीय लोगों के अनुसार सोलर बैटरियों का बैकअप बेहद सीमित था और कुछ घंटों के बाद पूरा इलाका फिर अंधेरे में डूब जाता था, बरसात और बादल वाले मौसम में स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती थी, मोबाइल चार्जिंग, बच्चों की पढ़ाई और रात के समय जरूरी कामों में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, कई गांवों में स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था भी बिजली के अभाव में प्रभावित होती रही।

इन गांवों और पाराओं तक पहुंचेगी बिजली

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के बहरासी सब स्टेशन से रामगढ़ क्षेत्र के कई गांवों और पाराओं तक नियमित बिजली पहुंचाई जाएगी, परियोजना में शामिल प्रमुख गांव और पारा इस प्रकार हैं, नटवाही, चुलांदर, रामगढ़, एतवार, सिंघोर, पश्चिमपारा, खैरवारीपारा,उज्जावं,अमृतपुर और भरतपुर ब्लॉक का ग्राम छाप इन सभी क्षेत्रों में पहली बार नियमित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था विकसित की जाएगी।

वनांचल का प्रशासनिक केंद्र है रामगढ़-रामगढ़ क्षेत्र केवल ग्रामीण इलाका नहीं, बल्कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र भी है, यहां कई प्रमुख सरकारी कार्यालय संचालित हैं, जिनमें, पुलिस चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप तहसील कार्यालय, वन परिक्षेत्र कार्यालय, और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति शामिल हैं, बिजली पहुंचने के बाद इन संस्थानों की कार्यप्रणाली में बड़ा सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं, दस्तावेजी कार्य और प्रशासनिक गतिविधियों में सुविधा बढ़ेगी।

भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी की सक्रियता लाई रंग

इस बड़ी उपलब्धि के पीछे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, देवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में स्थानीय प्रतिनिधियों ने लगातार शासन और विभागीय अधिकारियों के सामने वनांचल क्षेत्र की बिजली समस्या को उठाया, बताया गया कि भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपकर इस क्षेत्र में नियमित बिजली व्यवस्था की मांग की थी, इस दौरान मंडल अध्यक्ष राजाराम राजवाड़े, जिला पंचायत सदस्य शिव कुमारी सोनपाकर, जिला मंत्री ईश्वर, जनपद अध्यक्ष आशा देवी सोनपाकर, जी राजवाड़े, मनोज साहू और सुरेश राजवाड़े सहित कई जनप्रतिनिधि सक्रिय रूप से जुड़े रहे।

एमडी भीम सिंह कंवर की पहल से बढ़ी प्रक्रिया

मामले को गति तब मिली जब भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने रायपुर में बिजली विभाग के एमडी भीम सिंह कंवर से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं को विस्तार से रखा, मामले की गंभीरता को देखते हुए एमडी ने स्वयं रामगढ़ क्षेत्र का दौरा किया और जमीनी हालात का निरीक्षण किया, इसके बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा तेजी से सर्वे कराया गया और कुछ ही समय में 14.88 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी गई, फिलहाल टेंडर और एनओसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

परियोजना में क्या-क्या होगा शामिल

राजेश लकड़ा के अनुसार इस परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर विद्युत ढांचा विकसित किया जाएगा, परियोजना में शामिल होंगे, 87 किलोमीटर हाईटेंशन लाइन, 66 किलोमीटर लो टेंशन लाइन, 32 नए ट्रांसफार्मर, और जंगल क्षेत्र से होकर विशेष तकनीकी विद्युत विस्तार कार्य, अधिकारियों के अनुसार यह कार्य तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

शिक्षा और स्वास्थ्य को मिलेगा बड़ा लाभ- बिजली पहुंचने का सबसे बड़ा फायदा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा, बच्चों को अब रात में बेहतर रोशनी मिलेगी, जिससे पढ़ाई आसान होगी, स्कूलों में डिजिटल शिक्षा और तकनीकी संसाधनों का उपयोग बढ़ सकेगा, वहीं स्वास्थ्य केंद्रों में, वैक्सीन संरक्षण,बिजली आधारित चिकित्सा उपकरण, रात में इलाज, और आपातकालीन सेवाएं बेहतर तरीके से संचालित हो सकेंगी।

वनांचल में शुरू होगा विकास का नया दौर

गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के गांवों तक बिजली पहुंचाने की यह योजना केवल तार और ट्रांसफार्मर लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हजारों लोगों के जीवन में बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है,दशकों से अंधेरे में जीवन जी रहे ग्रामीणों के लिए यह परियोजना नई उम्मीद,बेहतर भविष्य और विकास की नई रोशनी लेकर आने वाली है, अब लोगों को उस दिन का इंतजार है जब पहली बार उनके गांवों की गलियां नियमित बिजली की रोशनी से जगमगाएंगी और वनांचल का अंधेरा इतिहास बन जाएगा।

ग्रामीणों में खुशी और उम्मीद का माहौल

नियमित बिजली मिलने की खबर के बाद पूरे रामगढ़ क्षेत्र में खुशी का माहौल है, ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक अंधेरे में जीवन बिताया, लेकिन अब उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य रोशनी से जुड़ने जा रहा है, स्थानीय लोगों ने इसे वनांचल के विकास का नया अध्याय बताया है।

अंतिम व्यक्ति तक विकास का उदाहरण

स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीति और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन मॉडल का उदाहरण बताया है, उनका कहना है कि सरकार अब उन क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रही है जो दशकों से विकास की मुख्यधारा से दूर रहे।

पेट्रोल-डीजल बचाओ अपील का असर या आस्था का महाकुंभ?

चिरमिरी की रामकथा में बसों-गाड़ियों से उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

जगद्गुरु रामभद्राचार्य की रामकथा में सरगुजा संभाग से उमड़ी आस्था

-संवाददाता-

एमसीबी/चिरमिरी 17 मई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग के चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों धर्म, आस्था और राजनीति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, प्रसिद्ध कथावाचक रामभद्राचार्य की विशाल रामकथा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित भव्य कलश यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी,आयोजन में सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और पूरे चिरमिरी क्षेत्र में भगवामय वातावरण नजर आया।

बसों और चार पहिया वाहनों में पहुंचे श्रद्धालु- कार्यक्रम में सबसे खास दृश्य यह देखने को मिला कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु निजी दोपहिया वाहनों की बजाय बसों और चार पहिया वाहनों के माध्यम से आयोजन स्थल पहुंचे, इसे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील से जोड़कर भी देखा, आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं को सामूहिक रूप से बसों और अन्य वाहनों में बैठाकर कथा स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी, रविवार को चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में चारों तरफ वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं, हालांकि भीड़ के बावजूद यह देखने को मिला कि अधिकांश वाहन बसें और चार पहिया थे, जिनमें सीट क्षमता के अनुसार श्रद्धालु बैठकर पहुंचे, इससे सड़क पर दोपहिया वाहनों की अपेक्षाकृत कम संख्या दिखाई दी।

महीनों से चल रही थी तैयारियां- चिरमिरी में आयोजित इस विशाल रामकथा कार्यक्रम की तैयारियां कई महीनों से चल रही थीं,आयोजक समिति द्वारा पूरे सरगुजा संभाग में जाकर आमंत्रण वितरित किए गए थे और श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई थी, कलश यात्रा को भव्य स्वरूप देने के लिए विशेष ड्रेस कोड भी तय किया गया था,महिला श्रद्धालुओं के लिए एक समान रंग की साड़ियों की व्यवस्था आयोजक समिति द्वारा की गई थी,जब हजारों महिलाएं एक जैसी साड़ियों में सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुईं तो पूरा वातावरण भक्तिमय और आकर्षक नजर आया।

भाजपा नेताओं और मंत्रियों की भी रही सक्रिय मौजूदगी-कलश यात्रा और रामकथा आयोजन के दौरान धार्मिक आयोजन के साथ-साथ राजनीतिक रंग भी साफ तौर पर दिखाई दिया, सरगुजा संभाग भर के भाजपा नेताओं का जमावड़ा कार्यक्रम में नजर आया। कई भाजपा नेता श्रद्धालुओं के साथ पैदल यात्रा करते दिखे,प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी कलश यात्रा में पैदल शामिल होकर श्रद्धालुओं का अभिवादन करते नजर आए,चिरमिरी भाजपा नेताओं ने आयोजक की भूमिका निभाते हुए बाहर से आए श्रद्धालुओं और अतिथियों के स्वागत की जिम्मेदारी संभाली,वहीं संभाग भर से पहुंचे भाजपा नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आयोजन को राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बना दिया।

दस दिनों तक चलेगा धार्मिक आयोजन

रामकथा कार्यक्रम पूरे दस दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, आयोजन स्थल पर धार्मिक प्रवचनों के साथ भजन, पूजा-अर्चना और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, कलश यात्रा के दौरान जिस तरह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, उसने साफ कर दिया कि चिरमिरी का यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के लिए आस्था का महाकुंभ बन चुका है। श्रद्धा, संगठन और राजनीतिक उपस्थिति– तीनों ने मिलकर इस आयोजन को भव्यता प्रदान की है।

ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी का खुलासा...गांधीनगर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार,चोरी की ट्रॉली और छोटा हाथी वाहन जब्त

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,17 मई 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी गई ट्रॉली तथा घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी वाहन भी बरामद कर लिया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अमित कुमार ठाकुर पिता ध्रुव कुमार ठाकुर निवासी गोधनपुर अंबिकापुर ने थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर के पीछे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात चोर 9 मई 2026 को चोरी कर ले गए। मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 280/2026 के तहत धारा 305बी एवं 3(5) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास पूछताछ करने के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में सामने आया कि चोरी की गई ट्रॉली को Ashok Leyland छोटा हाथी में ले जाया गया था। इसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी ब्रिजभूषण उर्फ बिरजू गिरी

निवासी ककना को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपने साथी फुलचंद गिरी और नंदू उर्फ नंदकिशोर पैकरा के साथ मिलकर गोधनपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी ब्रिजभूषण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अशोक लीलैंड कंपनी का छोटा हाथी वाहन क्रमांक यूपी 64 एटी 8637 तथा चोरी की गई ट्रॉली क्रमांक CG16 ZD0130 बरामद कर जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में ब्रिजभूषण उर्फ बिरजू गिरी पिता महेंद्र गिरी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम ककना चौकी बरियों थाना राजपुर जिला बलरामपुर,फुलचंद गिरी पिता शिवप्रसाद गिरी उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम केपी थाना अंबिकापुर तथा नंदू उर्फ नंदकिशोर पैकरा पिता महेश्वर पैकरा उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम ककना चौकी बरियों थाना राजपुर जिला बलरामपुर शामिल हैं। पूरी कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक सुभाष ठाकुर,आरक्षक कुंदन पांडेय,रमन मंडल,घनश्याम देवांगन, राहुल सिंह एवं साइबर सेल के आरक्षक रमेश रजवाड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

नाम परिवर्तन सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निमिष अग्रवाल, पिता श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, निवासी 8/5, अम्बेडकर चौक, जवाहर नगर, अम्बिकापुर (छ.ग.) का स्थायी निवासी हूँ। मेरे पूर्व के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम निमिष कुमार तथा निमिष कुमार अग्रवाल अंकित है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर निमिष अग्रवाल कर लिया है, जो कि वर्तमान में मेरे सभी पहचान पत्रों एवं अभिलेखों में दर्ज है। अतः भविष्य में मेरे समस्त कार्यों हेतु मेरा नाम निमिष अग्रवाल ही मान्य किया जाए। इस हेतु मैं अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है।

दिनांकः-10.04.2026

सत्यापनकर्ता
निमिष अग्रवाल
आ. वेद प्रकाश अग्रवाल
8/5, अम्बेडकर चौक, जवाहर नगर,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर (छत्तीसगढ़)
नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि बलरामपुर वनमण्डल के अंतर्गत काष्ठागार वाड्रफनगर में रखी इमारती लकड़ी / जलाऊ काष्ठ को निम्नलिखित तिथि व समय में ई-ऑक्शन द्वारा निवर्तन किया जाना है। इच्छुक व्यापारी ई-ऑक्शन में अवश्य भाग लेवें। ई-ऑक्शन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय अथवा काष्ठागार वाड्रफनगर से प्राप्त कर सकते हैं।

डिपो का नाम- काष्ठागार वाड्रफनगर
ई-नीलाम दिनांक 26.05.2026
समय-प्रातः 09:00 बजे से

क्र0	वनोपज का विवरण	नया काष्ठ		पुराना काष्ठ	
		लट्ठा	बल्ली / डेंगरी	लट्ठा (घ.मी.)	बल्ली / डेंगरी
		घ.मी.	नग	नग	
1	2	3	4	5	
A	ईमारती काष्ठ				
1	सागौन	-	-	82.167	190
2	साल	769.727	712	2223.516	226
3	साजा	7.178	28	257.967	104
4	तिन्सा	-	-	-	-
5	बीजा,शीशम,खम्हार	-	-	19.897	9
6	हल्दु,मुडी,बांसा	4.076	-	67.255	4
7	धावड़ा	2.708	5	7.542	76
8	अन्य मिश्रित (सेमल)	9.095	22	71.859	87
9	नीलगिरि	2.455	01	-	-
10	सलया	-	-	-	-
11	खैर काष्ठ	-	-	-	-
	योगः-	**795.239**	768	**2730.203**	**696**
क्रं.	प्रजाति विवरण				
1	जलाऊ चट्टा मिश्रित प्रजाति सा. 2.00मी x1.25 x 0.80 मी	506 चट्टा		402 चट्टा	

टीपः- 1. क्रेता को ई-ऑक्सन के पूर्व एम. एस. टी. सी. ई- कोमर्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2. क्रेताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व क्रय लाटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है। सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत ई. एम. डी. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
3. लॉट की थप्पी एवं फोटो एम.एस.टी.सी. ई-कॉमर्स पोर्टल में अपने आई.डी. से लॉगईन करके देख सकते हैं।

जी नंबर-262700771/4

वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर सजा सांस्कृतिक रंगारंग आयोजन

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,17 मई 2026 (घटती-घटना)।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर आदयाबंग समिति द्वारा पंचानन परिसर में भव्य 'गीत बिताना' सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री के.एस. कथूर, श्री मंगल पांडे, अभय तिवारी, राजनारायण द्विवेदी, हरिशंकर सिंह एवं जयप्रकाश चौबे की उपस्थिति में गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। समिति की संस्थापिका वंदना दत्ता ने स्वागत उद्बोधन में बताया कि आदया संस्था वर्ष 2013 से लगातार गुरुदेव की जयंती पर सांस्कृतिक आयोजन करती आ

रही है। उन्होंने कहा कि रवीन्द्र संगीत केवल गीत नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं की अमूल्य धरोहर है। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि 'चूल्हे से लेकर अंबर तक अब उसने परचम लहराया है' जैसी पंक्तियां आज समाज की महिलाओं द्वारा सार्थक की जा रही हैं। कार्यक्रम की शुरुआत श्रुति मुखर्जी, लिली बसु, हेना सेन, आतिशी भट्टाचार्य, सविता आइच, अनिमा मजूमदार, राखी चक्रवर्ती, पोम मुखर्जी एवं संगीता मुखर्जी द्वारा सामूहिक रूप से प्रस्तुत रवीन्द्र संगीत 'हे नुतोन देखा दिक' से हुई, जिसने वातावरण को भावविभोर कर दिया। बाल कलाकारों ने भी अपनी प्रतिभा से सभी का मन मोह लिया। मान्या गुहा ने 'आये सोखी शोहोचोरी ', ईशिका पाल ने 'आमार नोतुन जोऊ बोनेर' तथा नन्ही गायिका शौभिक बसु ने 'आलोकरे आई झोरना धारा' की सुंदर प्रस्तुति दी। प्रतीक विश्वास एवं प्रगति विश्वास ने 'एकला चलो रे' गीत की प्रस्तुति देकर खूब सराहना बटोरी। वहीं अंकित विश्वास ने रवीन्द्र संगीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। संचिता धर ने 'आमार सोनार होरीन चाई' गीत प्रस्तुत किया, जबकि भानु प्रकाश मुखर्जी एवं सुजाता पॉल ने भी मधुर रवीन्द्र संगीत से कार्यक्रम में समां बांध दिया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण सुप्रियो मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत एकांकी 'दीन दान' रहा, जिसका निर्देशन एवं नेपथ्य संचालन अनामिका वर्मा चक्रवर्ती ने किया। इसी क्रम में पोम मुखर्जी, राखी चक्रवर्ती, वर्षा गुहा एवं मृदु छाया गुहा ने 'ऐशो हे बोइशाख ऐशो ऐशो' पर शानदार सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। आदया की बहनों द्वारा 'आमार बेला जे जाए सांझ बेला ते' की सामूहिक प्रस्तुति भी दर्शकों को खूब पसंद आई। संगीत में भानु शंकर झा एवं नीरज शुक्ला ने संगत दी, जबकि कार्यक्रम का सफल संचालन अनामिका चक्रवर्ती ने किया। मुख्य अतिथि श्री कथूर ने संस्था के इस सतत आयोजन की सराहना करते हुए भविष्य में 'वसंत उत्सव' आयोजित करने का सुझाव दिया।

नारियल फूटे तीन बार, सड़क नहीं बनी एक बार!

सड़क से ज्यादा मजबूत निकली राजनीति की रिटेनिंग वॉल

विकास रास्ता पूछता रहा, नेता भूमिपूजन करते रहे, जनता को गड्ढे मिले, नेताओं को फोटो...

तीन-तीन भूमिपूजन, फिर भी सड़क गायब! 7.40 करोड़ का विकास 'सियासी गड्ढे' में दफन

भूमिपूजन की राजनीति में फंसी सड़क, 5 साल में तीन शिलान्यास लेकिन ग्रामीण अब भी बेहाल

- नेताओं के 'खास' बचाने रुकी सड़क? गोबरी पुल टूटा, बरसात से पहले बढ़ी ग्रामीणों की चिंता
- 7.40 करोड़ की सड़क पर राजनीति का रोलर! जनता धूल फांक रही, नेता फीता काट रहे
- गोबरी पुल टूटा, सड़क अधूरी, राजनीति पूरी, विकास के नाम पर ग्रामीणों के साथ बड़ा खेल?

- सड़क कम, सियासत ज्यादा! नेताओं के रसूख में अटका गंगौटी-शिवपुर मार्ग निर्माण...
- जनता पूछ रही—सड़क बनेगी कब? तीन भूमिपूजन के बाद भी अधूरा पड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट...
- रसूखदारों के मकान बचाने सड़क की चौड़ाई कम करने की तैयारी? ग्रामीणों में भारी आक्रोश...
- विकास का 'ब्रेकिंग पॉइंट': पुल टूटा, सड़क रुकी और राजनीति दौड़ती रही...
- जनपद सदस्य या सुपर इंजीनियर? सड़क रुकी, ग्रामीण फंसे और राजनीति गर्म...

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/भैयाथान, 17 मई 2026 (घटती-घटना)।

विकास की राजनीति करने वाले नेताओं के भाषणों में सड़कें बड़ी तेजी से बन जाती हैं,मंच पर नक्शे तैयार हो जाते हैं,नारियल फूट जाते हैं,फोटो खिंच जाती हैं और जनता को भरोसा दिला दिया जाता है कि अब गांव की किस्मत बदलने वाली है,लेकिन भैयाथान ब्लॉक का गंगौटी-शिवपुर नवापारा मार्ग देखकर ऐसा लगता है कि यहां सड़क कम और राजनीति ज्यादा बनाई गई है,करीब ?7 करोड़ 40 लाख की लागत से बनने वाली यह सड़क आज खुद सरकारी दावों और सियासी खेल का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है,पांच साल में इस सड़क का तीन-तीन बार भूमिपूजन हुआ,लेकिन सड़क आज भी अधूरी पड़ी है,जनता पूछ रही है कि आखिर यह सड़क बनेगी कब? या फिर हर चुनाव में सिर्फ इसका नया भूमिपूजन ही होता रहेगा? पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने अपने कार्यकाल में इस सड़क का दो बार भूमिपूजन किया,सत्ता बदली तो वर्तमान कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी बड़े तामझाम के साथ तीसरी बार भूमिपूजन कर दिया, लेकिन जमीन पर आज भी धूल उड़ रही है, गड्ढे पड़े हैं और अधूरी रिटेनिंग वॉल विकास के दावों पर हंसती नजर आ रही है,करीब 5 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी प्रस्तावित इस सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराया जाना था,लेकिन अब यह सड़क निर्माण से ज्यादा राजनीतिक संघर्ष, रसूखदारों की सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक बन चुकी है।

विकास की सड़क पर राजनीति का ब्रेकर

ग्रामीणों का आरोप है कि जब सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ, तभी से राजनीति ने उसमें ऐसा ब्रेक लगाया कि काम दोबारा गति ही नहीं पकड़ सका,इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा जनपद सदस्य राजू कुमार गुप्ता के नाम की हो रही है,गांवों में लोग व्यंग्य में उन्हें 'पीडब्ल्यूडी का सुपर इंजीनियर' कहने लगे हैं,आरोप है कि वे खुद को विभागीय अधिकारी से कम नहीं समझते और सड़क निर्माण में लगातार दखल देते रहे,जब सड़क निर्माण शुरू हुआ,तब उन्होंने निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाते हुए काम रुकवा दिया,अगर गुणवत्ता खराब थी, तो सवाल उठाना गलत नहीं था,लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसके बाद सड़क दोबारा शुरू कराने के लिए आखिर क्या किया गया? ग्रामीणों का कहना है कि काम रुकवाना आसान था,लेकिन सड़क पूरी हो सके,इसके लिए किसी ने गंभीर पहल नहीं की,अब बरसात सिर पर है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है,लेकिन जिम्मेदार लोग अब भी राजनीति में व्यस्त हैं,सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र में यह चर्चा भी जोरों पर है कि राजू कुमार गुप्ता खुद इस निर्माण कार्य में रुचि रखते थे,लेकिन ठेकेदार द्वारा उन्हें काम में हिस्सेदारी नहीं मिलने के कारण वे लगातार निर्माण में अड़ंगा बने हुए हैं,हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गांव-गांव में यही चर्चा सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है,एक ग्रामीण ने तंज कसते हुए कहा सड़क कम बनी,लेकिन नेताओं की राजनीति फोरलेन हो गई।

नेताओं के 'अपनों' का घर बचाने के लिए थमा काम?

सड़क निर्माण महीनों से बंद क्यों है? इस सवाल का जवाब तलाशने पर अंदरखाने से कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं,सूत्रों के अनुसार,सड़क के स्वीकृत नक्शे और चौड़ीकरण की जद में कुछ स्थानीय रसूखदार नेताओं के करीबियों के मकान और दुकानें आ रही हैं,यदि सड़क तकनीकी मानकों के अनुसार बनाई गई,तो कई पक्के निर्माणों पर बुलडोजर चल सकता है,यही कारण है कि कथित तौर पर पर्दे के पीछे से दबाव बनाकर काम रुकवा दिया गया,ग्रामीणों का आरोप है कि आम जनता की सुविधा को किनारे रखकर कुछ खास लोगों के मकानों को बचाने का खेल खेला जा रहा है, गांव के लोगों का कहना है कि गरीब किसानों की जमीन सड़क के लिए आसानी से ले ली गई, लेकिन जब नेताओं के करीबियों की दीवार सामने आई तो पूरा सिस्टम रुक गया।

अब सड़क नहीं,उसकी चौड़ाई काटने की तैयारी!

इस मामले में अब एक और चौंकाने वाली चर्चा तेजी से फैल रही है, कहा जा रहा है कि जिन हिस्सों में रसूखदारों के मकान आ रहे हैं,वहां सड़क की निर्धारित चौड़ाई ही कम करने की तैयारी चल रही है,यानी सड़क जनता की जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि नेताओं के करीबियों के घर बचाने के हिसाब से बनाई जाएगी! ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक सड़क के मास्टर प्लान और तकनीकी मानकों से खिलवाड़ कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है,यदि ऐसा हुआ,तो भविष्य में यह सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक समस्याओं का बड़ा कारण बन सकती है।

गरीब किसानों की जमीन गई,मुआवजा अब तक नहीं

इस सड़क निर्माण में करीब 57 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई, किसानों ने विकास के नाम पर अपनी जमीन दे दी,लेकिन बदले में उन्हें न सड़क मिली और न मुआवजा,ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बिजली की रफ्तार से पूरी कर ली गई,लेकिन मुआवजा भुगतान की फाइलें अब कछुए की चाल से भी धीमी चल रही हैं, एक किसान ने नाराजगी में कहा सरकार जमीन लेते समय हमें विकास का सपना दिखाती है,लेकिन बाद में वही किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रह जाता है।

गोबरी नदी का पुल टूटा,लेकिन जिम्मेदारों की नींद नहीं टूटी

इस पूरे मामले की सबसे भयावह तस्वीर गोबरी नदी का क्षतिग्रस्त पुल है, पिछले साल भारी बारिश में यह पुल टूट गया था। उसके बाद ग्रामीणों को 10 से 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर जिला और ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचना पड़ा, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी पुल की स्थिति जस की तस बनी हुई है, अब फिर मानसून सिर पर है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस बार भी सड़क और पुल का काम पूरा नहीं हुआ,तो करीब 10 हजार की आबादी का संपर्क कट जाएगा, सबसे ज्यादा खतरा मरीजों, गर्भवती महिलाओं और स्कूली बच्चों को होगा, ग्रामीणों का कहना है कि अगर बारिश के दौरान रास्ता बंद हो गया और किसी मरीज की जान चली गई,तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?

घटिया निर्माण का खेल रिटेनिंग वॉल में सरिया तक नहीं!

इस सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल उठ चुके हैं,आरोप है कि ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही रिटेनिंग वॉल में सरिया तक नहीं डाला जा रहा था और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था,मामला मीडिया में आने के बाद विभाग हरकत में आया, इंजीनियर विनोद सिंह मौके पर पहुंचे और अमानक निर्माण को रुकवाकर उसे तोड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बाद सड़क निर्माण सुधार के साथ आगे बढ़ने के बजाय पूरी तरह ठप्प पड़ गया,ग्रामीण पूछ रहे हैं कि यदि निर्माण में गड़बड़ी थी तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि कार्रवाई हुई, तो सड़क अब तक शुरू क्यों नहीं हुई?

ग्रामीणों ने दी आंदोलन और चक्काजाम की चेतावनी

गांव के लोगों में अब भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब आश्वासन नहीं,सड़क चाहिए,यदि मानसून से पहले सड़क और पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ तथा किसानों को मुआवजा नहीं मिला,तो वे उग्र आंदोलन और चक्काजाम करेंगे, एक ग्रामीण युवक ने गुस्से में कहा नेताओं के लिए सड़क चुनावी पोस्टर का बैकग्राउंड है,लेकिन हमारे लिए यह जिंदगी और मौत का रास्ता है।

विकास के नाम पर राजनीति का सबसे बड़ा गड्ढा

गंगौटी-शिवपुर नवापारा सड़क आज सिर्फ अधूरी सड़क नहीं,बल्कि उस व्यवस्था का आईना बन चुकी है जहां जनता की जरूरतें राजनीति के सामने छोटी पड़ जाती हैं, जहां गरीब किसान की जमीन आसानी से ले ली जाती है, लेकिन रसूखदारों की दीवार बचाने के लिए पूरा प्रोजेक्ट रोक दिया जाता है, जहां पुल टूटने के बाद भी सिस्टम नहीं जागता,जहां सड़क से ज्यादा भूमिपूजन होते हैं,और जहां विकास का मतलब जनता की सुविधा नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरण बन जाता है, अब देखना यह है कि प्रशासन मानसून से पहले जागता है या फिर इस बार भी बारिश के साथ ग्रामीणों की परेशानियां, सरकारी दावों की पोल और राजनीति का असली चेहरा सबके सामने बहकर आएगा।

जनता पूछ रही : नेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ नारियल फोड़ना है क्या?

अब ग्रामीण खुलकर सवाल पूछ रहे हैं।

- पहला सवाल :-जब इस सड़क का तीन-तीन बार भूमिपूजन हो चुका है,तो क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सिर्फ फोटो खिंचवाने और नारियल फोड़ने तक सीमित है?
- दूसरा सवाल :-क्या कुछ रसूखदार नेताओं के करीबियों के मकान बचाने के लिए 10 हजार ग्रामीणों की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है?
- तीसरा सवाल :-यदि बारिश में रास्ता बंद होने से किसी मरीज की मौत होती है,तो जिम्मेदार कौन होगा—पीडब्ल्यूडी विभाग, ठेकेदार या स्थानीय जनप्रतिनिधि?
- चौथा सवाल :-57 किसानों की जमीन अधिग्रहित करने के बाद भी मुआवजा भुगतान में इतनी देरी क्यों?
- पांचवां सवाल :- आखिर राजू कुमार गुप्ता पर लगाम कौन लगाएगा और सड़क निर्माण दोबारा कब शुरू होगा?

सरकारी गाड़ी बनी 'दारू एक्सप्रेस'!

मनेंद्रगढ़ आबकारी विभाग का नया मॉडल-'जहां बिक्री कम,वहां सरकारी गाड़ी दम'

सरकारी गाड़ी आखिर जनता के लिए है या 'स्टॉक एडजस्टमेंट' के लिए?

-रवि सिंह-

एमसीबी,17 मई 2026 (घटती-घटना)। सरकारी वाहन...नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनती है जिसमें कोई अधिकारी निरीक्षण पर जा रहा हो,कोई टीम छापेमारी कर रही हो, या फिर कोई प्रशासनिक कार्य हो रहा हो, लेकिन मनेंद्रगढ़ में सरकारी गाड़ी का एक नया और अनोखा उपयोग सामने आया है,यहां सरकारी वाहन अब सिर्फ अधिकारियों को ढोने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि शराब की पेटियां ढोने का भी जिम्मा निभाते नजर आए, मंगलवार रात मनेंद्रगढ़ में जो दृश्य देखने को मिला, उसने आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए, आरोप है कि विभागीय उपयोग के लिए उपलब्ध सरकारी वाहन का इस्तेमाल केल्हारी शराब दुकान से मनेंद्रगढ़ शराब दुकान तक शराब की पेटियां पहुंचाने में किया गया, मजेदार बात यह रही कि जब इस पूरे मामले पर सवाल उठे तो जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे कोई बड़ी बात मानने के बजाय बेहद सामान्य प्रक्रिया बताने की कोशिश की, अब जनता पूछ रही है क्या आबकारी विभाग में अब 'जहां शराब नहीं बिके, वहां सरकारी गाड़ी भेजो' योजना शुरू हो चुकी है?

रात के अंधेरे में चली 'दारू डिलीवरी सेवा'

मंगलवार रात लगभग 9:30 बजे मनेंद्रगढ़ अंग्रेजी शराब दुकान के बाहर अचानक एक सरकारी वाहन पहुंचता है, आसपास मौजूद लोग पहले तो समझे कि शायद कोई जांच या निरीक्षण होने वाला है, लेकिन थोड़ी ही देर में गाड़ी से शराब की पेटियां उतरने लगीं, लोगों की हैरानी उस वक्त और बढ़ गई जब पता चला कि यह कोई मालवाहक वाहन नहीं,बल्कि विभागीय उपयोग का सरकारी वाहन था, अब आम आदमी तो यही समझता है कि शराब परिवहन के लिए अलग वाहन,अलग अनुमति और अलग प्रक्रिया होती होगी। लेकिन मनेंद्रगढ़ में लगता है कि 'व्यवस्था' नियम पुस्तिका से नहीं, मौके की जरूरत से चलती है।

नियमों की किताब बनाम 'व्यवस्था का ज्ञान' में नियम में मना नहीं वाला तर्क कितना सही?- प्रशासनिक व्यवस्था केवल उन नियमों से नहीं चलती जिनमें 'मना' लिखा हो, बल्कि उन सिद्धांतों से भी चलती है जिनमें सरकारी संसाधनों के उचित उपयोग की भावना शामिल होती है, यदि यही तर्क हर विभाग अपनाने लगे कि 'कहीं मना नहीं लिखा ', तो फिर सरकारी गाड़ियों का उपयोग किसी भी काम में किया जा सकता है, व्यंग्य यही है कि अब शायद विभागों को नई गाइडलाइन जारी करनी पड़े, सरकारी वाहन से सब्जी नहीं लानी है, फर्नीचर नहीं ढोना है, निजी सामान नहीं पहुंचाना है, और अब शायद यह भी लिखना पड़े कि शराब की पेटियां भी नहीं ढोनी हैं।

शराब परिवहन क्या इतना आसान मामला है?- शराब कोई सामान्य वस्तु नहीं है, आबकारी विभाग में शराब की हर बोतल और हर पेटी का रिकॉर्ड रखा जाता है। स्टॉक, बिक्री, ट्रांसफर, बैच नंबर, टैक्स सब कुछ दस्तावेजों में दर्ज होता है, ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है क्या इस ट्रांसफर की लिखित अनुमति थी? क्या स्टॉक ट्रांसफर का रिकॉर्ड मौजूद है? क्या परिवहन के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन हुआ? क्या सरकारी वाहन को अधिकृत मालवाहक माना गया? यदि रास्ते में कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती? इन सवालों का जवाब फिलहाल धुंध में है, लेकिन विभाग का आत्मविश्वास साफ दिख रहा है।

सरकारी वाहन : अब 'मल्टीपर्पज सुविधा'- सरकारी गाड़ी का उपयोग किसलिए होता है, यह अब शायद विभागीय जरूरत तय करेगी, आज शराब की पेटियां ढोई जा रही हैं, कल शायद कोई और सामान भी 'जरूरत' के नाम पर ढोया जाए, क्योंकि जब तर्क यह हो कि 'नियम में मना नहीं है',तो फिर संभावनाएं असीमित हो जाती हैं, जनता अब मजाक में पूछ रही है क्या सरकारी वाहनों पर अब 'ऑन ड्यूटी' की जगह 'ऑन डिलीवरी' लिख दिया जाए?

सवाल सिर्फ शराब का नहीं, मानसिकता का है- इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात शराब की कुछ पेटियां नहीं, बल्कि वह सोच है जो इसे सामान्य मान रही है, यदि विभागीय अधिकारी खुद सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर इतने सहज हैं, तो नीचे स्तर पर क्या संदेश जाएगा? जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग नियमों की व्याख्या सुविधा अनुसार करने लगें, तो फिर विभागीय अनुशासन धीरे-धीरे मजाक बन जाता है।

सरकारी लॉगबुक क्या कहती है?- सरकारी वाहनों के उपयोग का रिकॉर्ड रखा जाता है, वाहन कहां गया, कितनी दूरी चली, किस काम से गई – सब दर्ज होता है, अब बड़ा सवाल यह है क्या उस वाहन की लॉगबुक में लिखा गया कि वह शराब ट्रांसफर करने गई थी? यदि लिखा गया, तो किस अधिकारी की अनुमति से? और यदि नहीं लिखा गया, तो फिर वाहन आखिर किस काम से दर्ज हुई? यानी मामला अब सिर्फ शराब की पेटियों का नहीं, सरकारी रिकॉर्ड की पारदर्शिता का भी बन चुका है।

आबकारी विभाग की 'रचनात्मक व्यवस्था'- मनेंद्रगढ़ का यह मामला अब लोगों के बीच व्यंग्य का विषय भी बन चुका है, लोग कह रहे हैं कि अब आबकारी विभाग सिर्फ शराब बेचने का काम नहीं करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद होम डिलीवरी भी करेगा, कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि सरकारी गाड़ी में शराब पहुंची है, कल को शायद ऑनलाइन डिलीवरी ऐप भी शुरू हो जाए, हालांकि यह व्यंग्य है, लेकिन इसके पीछे जनता का अविश्वास साफ दिखाई देता है।

नियमों से ज्यादा 'मैनेजमेंट' पर भरोसा?- यह पूरा मामला यह भी बताता है कि कई विभागों में अब काम नियम पुस्तिका से कम और 'मैनेजमेंट' से ज्यादा चल रहा है, जहां जो सुविधा दिखी, उसी से काम निकाल लिया गया, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था सुविधा से नहीं, प्रक्रिया से चलती है, क्योंकि एक बार प्रक्रिया कमजोर हुई तो फिर हर गलत काम के लिए एक नया बहाना तैयार हो जाता है।

अधिकारी का बयान,कुछ पेटी नहीं बिक रही थी, नियम में मना नहीं है...

जिला आबकारी अधिकारी के बयान ने बढ़ाया विवाद-इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा अब एमसीबी जिला आबकारी अधिकारी शशिकला पैकरा के उस बयान की हो रही है,जिसमें उन्होंने सरकारी वाहन से शराब ढोने की घटना को गलत मानने से लगभग इनकार कर दिया,मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि केल्हारी शराब दुकान में कुछ पेटी शराब की बिक्री नहीं हो रही थी,इसलिए उसे दूसरे शराब दुकान में शिफ्ट कर दिया गया, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल नहीं है जिसमें लिखा हो कि शराब को शासकीय वाहन में नहीं ढोया जा सकता, अब यही बयान पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, क्योंकि सवाल केवल शराब की कुछ पेटियों का नहीं, बल्कि प्रशासनिक सोच और सरकारी संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का है, यानी अब सरकारी वाहन सिर्फ निरीक्षण नहीं करेंगे, बल्कि 'सेल बढ़ाने' का काम भी करेंगे, अगर इसी तर्क को आगे बढ़ाया जाए तो आने वाले दिनों में शायद विभाग यह भी कह दे जहां ग्राहक कम होंगे, वहां सरकारी वाहन प्रचार वाहन बनकर जाएंगे।

'कुछ पेटी' का खेल या स्टॉक एडजस्टमेंट की कहानी?

सूत्रों की मानें तो मामला सिर्फ 'कुछ पेटियों' तक सीमित नहीं हो सकता। जानकारों का कहना है कि कई बार स्टॉक एडजस्टमेंट, कम बिक्री और रिकॉर्ड मैनेजमेंट के नाम पर कई तरह के खेल चलते हैं।हालांकि इस मामले में अभी किसी अवैध बिक्री या बड़े घोटाले का प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पूरा काम असामान्य तरीके से हुआ, अगर सब कुछ नियम अनुसार था तो रात में ही ट्रांसफर क्यों? सरकारी वाहन ही क्यों? अधिकृत परिवहन वाहन क्यों नहीं?

जनता की नजर में बढ़ी शंका

मनेंद्रगढ़ में अब इस पूरे मामले की चर्चा चाय दुकानों से लेकर बाजार तक हो रही है, लोगों का कहना है कि अगर आम आदमी सरकारी गाड़ी में शराब लेकर घूमता मिलता तो अब तक पुलिस केस दर्ज हो चुका होता, लेकिन यहां सरकारी गाड़ी खुद शराब पहुंचा रही है, ही वजह है कि मामला सिर्फ विभागीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रशासनिक विश्वसनीयता का विषय बन गया है।

क्या शासन लेगा संज्ञान?

अब निगाह शासन और वरिष्ठ अधिकारियों पर है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या मामले की जांच होगी? क्या वाहन उपयोग की समीक्षा होगी? क्या स्टॉक ट्रांसफर रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे? या फिर मामला 'कुछ पेटी नहीं बिक रही थी' कहकर खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि यदि इस तरह के मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो भविष्य में सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना और मुश्किल हो जाएगा।

आखिर में...

मनेंद्रगढ़ का यह मामला प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल छोड़ गया है, सरकारी वाहन जनता के टैक्स के पैसे से चलते हैं,उनका उपयोग जनहित और विभागीय कार्यों के लिए होना चाहिए, लेकिन जब वही वाहन शराब की पेटियां ढोते नजर आएं और अधिकारी उसे सामान्य बताते दिखें,तो सवाल उठना स्वाभाविक है, फिलहाल आबकारी विभाग के पास तर्क है शराब नहीं बिक रही थी,इसलिए दूसरी दुकान भेज दी, लेकिन जनता के पास भी एक सवाल है अगर हर विभाग इसी तर्क पर काम करने लगे, तो फिर सरकारी और निजी काम में फर्क आखिर बचेगा क्या? मनेंद्रगढ़ में इस वक्त यही चर्चा है कि सरकारी गाड़ी आखिर 'निरीक्षण वाहन' है या 'दारू एक्सप्रेस'।

संलग्न गुरुजी हुए असंलग्न! कलेक्टर के एक आदेश से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

एमसीबी में संलग्नीकरण पर चली कैंची,आदेश आते ही 'आका' तलाशने निकले शिक्षक

- प्रदेश में फिसड्डी बना एमसीबी,अब कलेक्टर का बड़ा एक्शन—18 शिक्षकों का संलग्नीकरण समाप्त
- बोर्ड रिजल्ट में आखिरी स्थान और फिर प्रशासन का वार,संलग्न शिक्षकों की व्यवस्था खत्म
- विद्यालय छोड़ कार्यालयों में जमे थे गुरुजी, खराब रिजल्ट के बाद कलेक्टर ने लौटाया स्कूल
- संलग्नीकरण समाप्त होते ही वायरल हुआ शिक्षकों का चैट,सिस्टम पर निकली भड़ास
- जुगाड़ से संलग्न,जुगाड़ से पुरस्कार? एमसीबी शिक्षा विभाग पर उठे बड़े सवाल
- संलग्न शिक्षक अब खोज रहे नए सहारे, आदेश के बाद विभागीय गलियारों में बेचैनी
- शिक्षा गुणवत्ता पुरस्कार पर भी सवाल,संलग्न शिक्षकों की भूमिका की जांच की मांग तेज
- एमसीबी में 'संलग्न संस्कृति' पर प्रशासन का प्रहार,अब जवाबदेही तय होने का इंतजार

शिक्षा विभाग में वर्षों से चल रही सुविधा व्यवस्था पर चला कलेक्टर का डंडा

-रवि सिंह-

एमसीबी,17 मई 2026 (घटती-घटना)। नवगठित एमसीबी जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच अब प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है, जिले की नव पदस्थ कलेक्टर ने शिक्षा विभाग में वर्षों से चली आ रही संलग्नीकरण व्यवस्था पर प्रहार करते हुए शिक्षकों के सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है,आदेश जारी होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एक साथ 18 शिक्षकों का संलग्नीकरण समाप्त किया गया है,इनमें वे शिक्षक भी शामिल हैं जो लंबे समय से अपने मूल विद्यालयों में पढ़ाने के बजाय विभिन्न कार्यालयों,परियोजनाओं, विभागीय शाखाओं और गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न होकर कार्य कर रहे थे,इस कार्रवाई को सीधे तौर पर जिले के बेहद खराब बोर्ड परीक्षा परिणाम से जोड़कर देखा जा रहा है,एमसीबी जिला इस वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में पूरे प्रदेश में अंतिम पायदान पर पहुंच गया। यही वह बिंदु बना जहां प्रशासन ने यह मान लिया कि अब केवल समीक्षा बैठकों और निर्देशों से काम नहीं चलेगा,बल्कि व्यवस्था में वास्तविक हस्तक्षेप करना होगा,कलेक्टर के इस फैसले ने शिक्षा विभाग की उस व्यवस्था को सीधे चुनौती दी है, जो वर्षों से 'संलग्नीकरण संस्कृति' के नाम पर चलती रही और धीरे-धीरे शिक्षा व्यवस्था को खोखला करती चली गई।

बोर्ड परीक्षा परिणाम ने खोल दी जिले की शिक्षा व्यवस्था की पोल- एमसीबी जिले का बोर्ड परीक्षा परिणाम इस बार प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों के लिए शर्मिंदगी का विषय बन गया,प्रदेश स्तर पर जारी परिणामों में जिला अंतिम स्थान पर पहुंच गया,यह केवल एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का आईना था जिसमें विद्यालयों में शिक्षकों की कमी लगातार बनी रही और बड़ी संख्या में शिक्षक स्कूल छोड़कर कार्यालयों और अन्य विभागों में संलग्न रहे,ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के कई स्कूलों में स्थिति यह रही कि बच्चों को नियमित विषय शिक्षक तक उपलब्ध नहीं हो सके, कई जगह एक या दो शिक्षक पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी संभालते रहे,जबकि दूसरी तरफ कुछ शिक्षक वर्षों तक ब्लॉक, जिला कार्यालयों और अन्य संस्थानों में संलग्न होकर अपेक्षाकृत सुविधाजनक माहौल में कार्य करते रहे, अब जब परीक्षा परिणाम सामने आया,तो सबसे पहले यही सवाल उठा कि आखिर पढ़ाई कौन कराएगा यदि शिक्षक विद्यालयों में रहेंगे ही नहीं? यही कारण है कि नव पदस्थ कलेक्टर ने अपनी प्रारंभिक समीक्षा में ही इस व्यवस्था को शिक्षा गुणवत्ता गिरने का एक बड़ा कारण माना और तत्काल प्रभाव से संलग्नीकरण समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।

आदेश जारी होते ही संलग्न शिक्षकों में बेचैनी- संलग्नीकरण समाप्ति का आदेश सामने आते ही शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई, सूत्र बताते हैं कि वर्षों से संलग्न व्यवस्था का लाभ ले रहे कई शिक्षक अचानक असहज स्थिति में आ गए। कुछ शिक्षकों को अब अपने मूल विद्यालयों में वापस लौटना पड़ेगा,जिनमें कई दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल भी शामिल हैं,इधर विभागीय गलियारों में यह चर्चा भी शुरू हो गई कि कई शिक्षक अब नए 'आका' की तलाश में सक्रिय हो गए हैं,कहा जा रहा है कि कुछ लोग राजनीतिक संपर्कों, कुछ विभागीय प्रभाव और कुछ प्रशासनिक जुगाड़ के माध्यम से फिर से संलग्न होने की कोशिश में लग गए हैं,यानी आदेश ने केवल प्रशासनिक हलचल नहीं पैदा की, बल्कि वर्षों से बनी एक 'आरामदायक व्यवस्था' को भी हिला दिया है।

संलग्नीकरण-सुविधा या शिक्षा व्यवस्था पर बोझ?- शिक्षकों का संलग्नीकरण मूल रूप से अस्थायी प्रशासनिक आवश्यकता के लिए बनाया गया प्रावधान माना जाता है, लेकिन धीरे-धीरे कई जिलों में यह व्यवस्था 'सुविधा संस्कृति' में बदलती चली गई, कई शिक्षक विद्यालयों में पढ़ाने के बजाय कार्यालयीन कार्यों, योजनाओं, सर्वेक्षणों, विभागीय समन्वय, डाटा एंट्री और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में वर्षों तक संलग्न रहे, इस व्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान स्कूलों और विद्यार्थियों को उठाना पड़ा, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बढ़ती गई, पढ़ाई प्रभावित होती गई और परीक्षा परिणाम लगातार गिरते गए, एमसीबी जिले का ताजा परिणाम उसी व्यवस्था का परिणाम माना जा रहा है।

संलग्न रहते हुए मिला 'शिक्षा गुणवत्ता पुरस्कार',अब उठ रहे सवाल- इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उन शिक्षकों को लेकर हो रही है जिन्हें विद्यालयों में नियमित शिक्षण कार्य न करने के बावजूद 'शिक्षा गुणवत्ता पुरस्कार' तक मिल गए, बताया जा रहा है कि कुछ शिक्षक अन्य विभागों में संलग्न रहकर कार्यालयीन कार्य करते रहे, लेकिन पुरस्कार ऐसे मिले जैसे उन्होंने विद्यालयों में रहकर शिक्षा स्तर में बड़ा सुधार किया हो, अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे हुआ? क्या बिना नियमित पढ़ाई कराए भी 'उत्कृष्ट शिक्षक' बना जा सकता है? क्या पुरस्कार वास्तविक कार्य के आधार पर दिए गए या फिर यह भी जुगाड़ व्यवस्था का हिस्सा था? अब इन पुरस्कारों की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठने लगी है।

वायरल व्हाट्सऐप चैट ने बढ़ाई चर्चा- संलग्नीकरण समाप्ति के बाद कथित रूप से कुछ शिक्षकों का व्हाट्सऐप चैट सोशल मीडिया में वायरल हो गया, इस चैट में कई शिक्षक आदेश को लेकर नाराजगी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, कुछ व्यवस्था को कोस रहे हैं, कुछ प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ अन्य कर्मचारियों के संलग्नीकरण का मुद्दा उठा रहे हैं, सबसे दिलचस्प बात यह बताई जा रही है कि जो शिक्षक वर्षों तक संलग्न व्यवस्था का लाभ लेते रहे, वही अब दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के संलग्नीकरण पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इस वायरल चैट ने शिक्षा विभाग के भीतर चल रही बेचैनी को सार्वजनिक कर दिया है।

जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका पर भी उठे सवाल- बोर्ड परीक्षा परिणाम खराब आने के बाद अब जिला शिक्षा विभाग के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि यदि जिला पूरे प्रदेश में अंतिम स्थान पर पहुंच गया, तो इसकी जिम्मेदारी केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं मानी जा सकती, लोग पूछ रहे हैं जिले में शैक्षणिक मॉनिटरिंग कैसी थी? विद्यालयों का निरीक्षण कितना हुआ? परिणाम सुधारने के लिए क्या रणनीति बनाई गई? संलग्नीकरण की समीक्षा क्यों नहीं हुई? जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं थे वहां व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? हालांकि विभागीय गलियारों में यह चर्चा भी है कि संलग्नीकरण समाप्ति के आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने राहत महसूस की, क्योंकि प्रारंभिक कार्रवाई का फोकस शिक्षकों पर चला गया और उच्च स्तर की जवाबदेही पर तत्काल चर्चा सीमित रह गई।

विद्यालय छोड़ कार्यालय संस्कृति ने बिगाड़ी व्यवस्था- एमसीबी जिले में लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि शिक्षा विभाग में 'विद्यालय छोड़ कार्यालय संस्कृति' विकसित हो गई थी, कुछ शिक्षक स्कूलों से ज्यादा समय कार्यालयों, बैठकों, योजनाओं और अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों में बिताने लगे थे, परिणाम यह हुआ कि बच्चों की बुनियादी पढ़ाई प्रभावित हुई, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जब शिक्षक विद्यालय में नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई, अनुशासन और परीक्षा तैयारी प्रभावित होना स्वाभाविक है, अब प्रशासन ने इसी संस्कृति पर पहला बड़ा प्रहार किया है।

पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने किया फैसले का स्वागत-

कलेक्टर के इस फैसले का पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने खुलकर स्वागत किया है, उन्होंने इसे समय की जरूरत बताते हुए कहा कि विद्यालयों में शिक्षक नहीं रहेंगे तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? उन्होंने कलेक्टर को धन्यवाद देते हुए कहा कि वर्षों से संलग्नीकरण के कारण स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और इसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा था, पूर्व विधायक के समर्थन के बाद यह मामला और अधिक राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का विषय बन गया है।

अब उठ रहा सबसे बड़ा सवाल – क्या होगी पुराने संलग्नीकरणों की जांच?-

संलग्नीकरण समाप्ति के बाद अब एक और बड़ा सवाल तेजी से उठने लगा है, क्या उन शिक्षकों के पूरे कार्यकाल की जांच होगी जो वर्षों तक विद्यालयों से दूर रहे? लोग पूछ रहे हैं किस आधार पर संलग्नीकरण किए गए? क्या वास्तव में प्रशासनिक आवश्यकता थी? क्या कुछ शिक्षक प्रभाव और पहुंच के कारण वर्षों तक संलग्न बने रहे? क्या नियमों का पालन हुआ? क्या ऐसे शिक्षकों की वजह से विद्यालयों में शिक्षण प्रभावित हुआ? इन सवालों ने अब पूरे शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

अब अगला इंतजार – खराब परिणाम वाले स्कूलों पर कार्रवाई का

संलग्नीकरण समाप्ति के बाद अब पूरे जिले की नजर अगले कदम पर है।

- क्या केवल संलग्न शिक्षक ही जिम्मेदार माने जाएंगे?
- क्या खराब परिणाम देने वाले विद्यालयों की अलग समीक्षा होगी?
- क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी?
- क्या भविष्य में फिर से 'जुगाड़ आधारित संलग्नीकरण' शुरू नहीं होगा?
- ये सवाल अब शिक्षा विभाग के सामने खड़े हैं।

नई कलेक्टर ने दे दिया बड़ा संदेश

नव पदस्थ कलेक्टर ने अपनी पहली ही बड़ी समीक्षा में यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब केवल कागजी सुधार और बैठकें पर्याप्त नहीं होंगी, यदि शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है तो शिक्षकों को विद्यालयों तक वापस पहुंचाना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी और वर्षों से चली आ रही सुविधाजनक व्यवस्थाओं पर रोक लगानी होगी, फिलहाल जिले में इस फैसले की चर्चा हर स्तर पर हो रही है, कुछ लोग इसे शिक्षा सुधार की दिशा में साहसिक कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे वर्षों से चली आ रही 'आरामदायक व्यवस्था' पर पड़ा पहला बड़ा प्रशासनिक प्रहार मान रहे हैं, अब देखना यह होगा कि यह कार्रवाई केवल आदेश तक सीमित रहती है या वास्तव में एमसीबी जिले की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और जवाबदेही तय करने की दिशा में आगे बढ़ती है।

CMYK

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में सुशासन तिहार के तहत 465 करोड़ रुपये के 102 विकास कार्यों की दी सौगात

सुशासन तिहार बना जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण और संवेदनशील प्रशासन का सशक्त माध्यम : मुख्यमंत्री साय

रायपुर,17 मई 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धमतरी में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जिलेवासियों को 465 करोड़ रुपये की लागत के 102 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री साय ने 423 करोड़ 52 लाख 56 हजार रुपये लागत के 52 कार्यों का भूमिपूजन तथा 41 करोड़ 50 लाख 48 हजार रुपये से अधिक लागत के 50 कार्यों का लोकार्पण किया। इन विकास कार्यों के माध्यम से जिले में सड़क, पेयजल, नगरीय अधोसंरचना और जनसुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और त्वरित समाधान की कार्यसंस्कृति के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 1 मई से 10 जून तक आयोजित सुशासन तिहार के माध्यम से गांव-गांव में क्लस्टरवार शिविर लगाकर आम नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया

जा रहा है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिससे हजारों लोगों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों,महिलाओं,युवाओं और गरीब परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने प्रशासनिक पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रारंभ की जाएगी,जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और समय-सीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एवं बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने नागरिकों से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील भी की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर संभाग में सुशासन तिहार के साथ 'बस्तर मुन्ने' और 'नियद नेल्लानार 2.0' अभियान भी संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। उन्होंने 'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर पहुंचकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं तथा जरूरतमंदों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में जनसहभागिता का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने आयुष्मान कार्ड एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को चाबी सौंपकर लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर 'ड्रीम कॉरिडोर' वीडियो एवं 'मां अभियान' की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन धमतरी एवं लर्निंग जॉय बेंगलुरु के मध्य एमओयू किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरीवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगातें दीं। उन्होंने अम्बेडकर चौक धमतरी से रूद्री चौक तक फोरलेन सड़क निर्माण, धमतरी में पेयजल हेतु इंटेकवेल निर्माण, रानी दुर्गावती चौक से बिलाईमाता मंदिर तक गौरवपथ निर्माण, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरूद भवन के लिए डेढ़ करोड़ रुपये तथा पीएमस्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। कार्यक्रम में सांसद महासमुंद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विधायक कुरूद अजय चन्द्राकर, विधायक धमतरी ओंकार साहू, महापौर रामू रोहरा, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद, रायपुर संभाग के कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में 20 को दवा विक्रेता हड़ताल

रायपुर,17 मई 2026। 20 मई को दवा विक्रेताओं के देशव्यापी हड़ताल को देखते खाद्य और औषधि प्रशासन ने वैकल्पिक इंतज़ाम किए हैं। इन जगहों पर दवाइयां मिलेंगी। ऑनलाइन औषधियों की बिक्री के विरोध स्वरूप विभिन्न केमिस्ट संगठनों द्वारा 20 मई 2026 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य में आम नागरिकों को आवश्यक औषधियों एवं स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रशासन द्वारा समस्त जिलों में अधिकारियों को आवश्यक जीवनरक्षक औषधियों, आपातकालीन स्वास्थ्य उत्पादों एवं चिकित्सकीय सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु

आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शासकीय जनऔषधि केन्द्रों , धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स, शासकीय चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स एवं अन्य औषधि वितरण केन्द्रों के माध्यम से आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आमजन एवं मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन को भी पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया गया है कि प्रस्तावित विरोध कार्यक्रम के दौरान जनहित, रोगी सेवा एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक दवाओं एवं स्वास्थ्य उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। आमजन से अपील की जाती है कि वे घबराहट अथवा अनावश्यक दवाओं का संग्रहण न करें।

रायपुर से दिल्ली तक सियासी बवाल : पेट्रोल के दामों पर भड़के भूपेश,सुशासन तिहार पर सरकार को घेरा

रायपुर,17 मई 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी से लेकर दिल्ली के गलियारों तक इस वक्त पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे को लेकर सीधे केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने साफ कहा कि देश में आज जो तेल के दामों को लेकर हाहाकार मचा है, उसकी पूरी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार है। जनता परेशान है और सरकार सोई हुई है।

दूसरों को सीख,खुद के लिए छूट

पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर तीखा तंज कसा है। बघेल ने एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हुए कहा, उपदेश कुशल बहुतेरे। उनका सीधा इशारा था कि केंद्र सरकार दूसरों को तो सादगी और

नियम कायदे सिखाती है,लेकिन खुद उन पर अमल नहीं करती। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि फिजूल की विदेश यात्राएं नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, वो खुद विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। बघेल ने सवाल उठाया कि आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? दूसरों के लिए अलग नियम और खुद के लिए अलग कानून क्यों चल रहा है? आज देश की जनता महंगाई से त्रस्त है और सरकार को जवाब देना ही होगा।

सुशासन तिहार पर सवाल

भूपेश बघेल सिर्फ केंद्र पर ही नहीं रुके, उन्होंने छत्तीसगढ़ की साय सरकार के सुशासन तिहार कार्यक्रम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक पकड़ पर गंभीर सवाल उठाए। बघेल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुशासन तिहार के नाम पर जिलों का दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। आम जनता से कोई ढंग से मिल नहीं पा रहा है। प्रदेश में प्रशासन किसी के भी नियंत्रण में नहीं रह गया है,अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं। भाजपा के अपने खुद के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं में भारी हताशा और निराशा का माहौल है। सुशासन के बड़े-बड़े दावों के बीच आम लोगों की सुनवाई दफ्तरों में नहीं हो रही है। पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम और छत्तीसगढ़ की स्थानीय सियासत को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक मूड में आ गई है। आने वाले दिनों में यह सियासी पारा और चढ़ने की उम्मीद है।

जनपद सभापति की गिरफ्तारी जल्द,सेक्स की डिमांड,अग्रिम जमानत याचिका खारिज

खैरागढ़,17 मई 2026। जिले की राजनीति में हड़कंप मच गया है, जिसकी वजह भाजपा से जुड़े जनपद सभापति सुधीर गोलछा पर महिला अधिकारी की ओर से लगाए गए गंभीर आरोप है। महिला अधिकारी का आरोप है कि आरोपी

लंबे समय से उन्हें परेशान कर रहा था, अश्लील बातें करता था, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था और विरोध करने पर धमकियां देता था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। वहीं अब उसकी अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। पीड़िता के मुताबिक,आरोपी अक्सर ऑफिस पहुंचकर अकेले में बात करने का दबाव बनाता था। प्रशासनिक चर्चा के बहाने कर्मचारियों को बाहर भेजने की कोशिश करता और निजी जीवन को लेकर अभद्र टिप्पणियां करता था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने धमकी भरे अंदाज में पूर्व CEO का हाल देख लिया है? जैसी बात कही,जिससे अधिकारी डर और तनाव में आ गईं। महिला अधिकारी ने बताया कि आरोपी लगातार मोबाइल पर कॉल करता था,गंदी बातें करता था और मिलने का दबाव बनाता था। जब उन्होंने नंबर ब्लॉक किया तो आरोपी ने वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत पहुंचा दी। इतना ही नहीं आरोपी ने उनके घर की जानकारी बताते हुए डराने की कोशिश भी की। काफी समय तक लोकलाज और बदनामी के डर से चुप रहने के बाद महिला अधिकारी ने आखिरकार छुईखदान थाना में शिकायत दर्ज कराई।

जनगणना में पिछड़े रायपुर-दुर्ग-रायगढ़ समेत शहरी जिले

रायपुर में 10%,रायगढ़ में 4.65% और भिलाई नगर में 7.84% हुआ काम,आदिवासी और ग्रामीण जिले आगे

रायपुर,17 मई 2026। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनगणना 2027 की तैयारियां चल रही हैं। राज्यभर में मकान सूचीकरण ब्लॉकों के गठन और सत्यापन का काम चल रहा है। जिसमें बड़े शहरों और नगर निगम क्षेत्रों की रफ्तार काफी धीमी है। राज्य सरकार की ताजा प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में अब तक 60.73% काम पूरा हो चुका है। कुल 48,742 मकान सूचीकरण ब्लॉकों में से 29,602 ब्लॉकों का सत्यापन और गठन पूरा कर लिया गया है। हालांकि राजधानी रायपुर, रायगढ़, दुर्ग-भिलाई जैसे शहरी जिले इस अभियान में काफी पीछे चल रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम सबसे निचले पायदान पर है, जहां सिर्फ 4.65% काम ही पूरा हो पाया है। वहीं भिलाई नगर में 7.84% और रिसाली में 8.33% कार्य पूरा हुआ है। राजधानी रायपुर की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है।

मुख्यमंत्री बोले...सटीक जनगणना से पहुंचेगा सुशासन

मुख्यमंत्री साय ने जनगणना कार्य की प्रगति पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि आगामी जनगणना 2027 के आंकड़े भविष्य की योजनाओं,विकास और जनकल्याणकारी नीतियों की मजबूत नींव बनेंगे। मुख्यमंत्री ने बड़े शहरों और नगर निगम क्षेत्रों में धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को मैदानी मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

जीपीएम ने मारी बाजी,जशपुर-मोहला भी आगे...

जहां शहरी इलाके पिछड़ रहे हैं, वहीं आदिवासी और ग्रामीण जिलों ने जनगणना तैयारियों में बाजी मार ली है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला 100% काम पूरा कर राज्य में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा जशपुर में 99.87% और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 99.84% काम पूरा हो चुका है। बेमेतरा में 97.8% और मुंगेली में 96.52% प्रगति दर्ज की गई है।

माइक्रो प्लानिंग से जीपीएम बना नंबर-1

जीपीएम कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने जिले की सफलता का श्रेय स्थानीय प्रगणकों और प्रशासनिक टीम को दिया। उन्होंने बताया कि दुर्गम और आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद माइक्रो प्लानिंग और रोजाना डिजिटल मॉनिटरिंग की मदद से 100% लक्ष्य हासिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अधिकांश जिलों में 'HLBs Not Started' का आंकड़ा शून्य है। यानी लगभग सभी जगह मैदानी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। सिर्फ कबीरधाम के एक ब्लॉक में काम शुरू नहीं हुआ है। अब नगर निगम आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि शहरी क्षेत्रों में लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए विशेष नोडल अधिकारी तैनात किए जाएं।

आकाशीय बिजली के चपेट में आने से 21 मवेशियों की मौत

बस्तर,17 मई 2026। बस्तर संभाग में मौसम का बदला मिजाज ग्रामीणों के लिए भारी पड़ गया। जगदलपुर और बीजापुर में आकाशीय बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में कुल 21 मवेशियों की मौत हो गई। इन हादसों के बाद प्रभावित गांवों में मातम और चिंता का माहौल है, क्योंकि पशुपालन ही कई परिवारों की आजीविका का मुख्य सहारा है। जगदलपुर शहर से लगे चिलकुटी गांव के सुरंगियापारा में शनिवार रात बारिश के दौरान बड़ा

हादसा हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक, कई मवेशी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। इसकी चपेट में आने से 11 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पशुपालकों में हड़कंप मच गया। शनिवार को दिनभर तेज गर्मी के बाद शाम में मौसम बदला था और शहर सहित आसपास के इलाकों में बारिश हुई थी। उधर, बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के पोन्दुम गांव में भी आकाशीय बिजली ने तबाही मचाई। शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे खेत और खुले स्थानों पर मौजूद 10 मवेशी बिजली गिरने की चपेट में आ गए। हादसे में सभी मवेशियों की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार,मृत मवेशियों में लक्ष्मण हपका, बुधराम हपका और दशरथ बघेल के दो-दो मवेशी शामिल हैं,जबकि पिंकी बघेल, सुंदरी हपका, आसमती हपका और मन्नू हपका के एक-एक मवेशी की जान गई है। अधिकांश मवेशी सफेद रंग के बताए जा रहे हैं। दोनों घटनाओं के बाद प्रभावित परिवारों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पशुपालन से ही उनके घर का खर्च चलता है और इतनी बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत ने उनकी कमर तोड़ दी है।

करही गोलीकांड : एसपी कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस,बदमाशों ने घर घुसकर युवक को मारी थी गोली

जांजगीर-चांपा,17 मई 2026। करही गोली कांड को अंजाम देने वाले आरोपी अबतक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। घटना में बेटे को खोने के बाद पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने 20 मई को जांजगीर एसपी कार्यालय के घेराव का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन सौंपा गया था। अगर दो दिन में आरोपी गिरफ्तारी नहीं होती है तो 20 मई को एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इधर, सक्ति जिले के प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए कहा है कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उन्होंने दावा किया कि घटना में शामिल आरोपियों को जल्द सलाखों भेजकर मामले का खुलासा किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला ?

पूरी वारदात बिर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत करही गांव की है। 23 अप्रैल की

करीब रात 12 बजे तीन अज्ञात नकाबपोश हमलावर घर के पीछे के रास्ते से व्यवसायी सम्मेलाल कश्यप के घर में घुसे। घर में घुसने के बाद वह सबसे पहले उस कमरे में पहुंचे, जहां आयुष, उसका भाई और एक बहन सो रहे थे। हमलावरों ने 19 वर्षीय आयुष कश्यप पर दो राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली सीने और दूसरी कनपटी पर लगी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, आशुतोष कश्यप पर भी एक राउंड फायर किया गया, जो उसके दाहिने हाथ में लगी। इस दौरान पैसों की मांग की बात भी सामने आई है। फिलहाल घायल आशुतोष को तत्काल जिला अस्पताल जांजगीर में भर्ती कराया जा रहा है।

राजनीति से भी जुड़ा है परिवार : मृतक आयुष कश्यप, सम्मेलाल कश्यप का बेटा था, जो हाल ही में रेत के कारोबार में शामिल था। बीती रात वह जांजगीर-चांपा में रेत गाड़ी को छुड़वाने गया हुआ था, वहां वह देर रात वापस लौटा था। सम्मेलाल कश्यप लोहा व्यापारी होने के साथ ही ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। वह पूर्व में उपसरपंच भी रह चुके हैं। वहीं उनकी पत्नी भी पूर्व सरपंच रह चुकी हैं।

कार ने कुचला.. सड़क पर तड़पकर 2 युवकों ने तोड़ा दम

दुर्ग-भिलाई,17 मई 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में तेज रफ्तार कार ने रेड सिग्नल पर खड़ी 2 बाइकों को कुचल दिया। हादसे में नाबालिग समेत 2 लोगों की मौत हो गई। जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। जिसका निजी अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। बाइक सवार एसी बनाने का काम करते हैं, वे कहीं रिपेयर के काम से जा रहे थे। रेड सिग्नल पर खड़े थे, तभी तेज रफ्तार कार ने पीछे से आकर उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दूर गिरे युवक सड़क पर तड़प रहे थे। गाड़ियों के परखच्चे भी उड़ गए थे। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस ने कार ड्राइवर सागर जायसवाल को हिरासत में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, दो अलग-अलग बाइक और स्कूटी पर 3 लोग सवार थे। वो सुपेला से पावर हाउस की तरफ जाते समय चंद्रामौर्या चौक पर रेड सिग्नल पर खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार(क्रमांक CG07BR0571) ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

मानवता शर्मसार...शराब पिलाकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म,इलाके में भारी आक्रोश

कवर्धा,17 मई 2026। कवर्धा गैंगरेप मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। छट्ठी कार्यक्रम से घर लौट रही युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। घटना के बाद पीड़िता अर्धनग्न और बेहोश हालत में मिली। पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है।

सुनसान रास्ता,बदला माहौल और फिर वारदात : युवती एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। देर रात वह घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में कुछ युवकों ने उसे रोका और शराब पिलाई। इसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। वारदात के बाद आरोपी उसे मौके पर छोड़कर भाग निकले। सुबह जब ग्रामीणों की नजर युवती पर पड़ी तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई। किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवती को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा रही। कई महिलाओं की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। एक स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि रात में तेज सन्नाटा था। दूर खेतों की तरफ

कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ दूरी पर इतनी बड़ी वारदात हो चुकी है। इलाज के दौरान पीड़िता ने पुलिस को शुरुआती जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाकर संदिग्धों की तलाश शुरू की। जांच के कुछ घंटों के भीतर दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। घटनास्थल से कुछ अहम सबूत भी जुटाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद मामले की तस्वीर और साफ होगी। घटना के बाद कवर्धा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात सुनसान रास्तों पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की जरूरत है।

C M Y K

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

आमचो बस्तर
बस्तर/मुन्ने

बस्तर में विकास

एवं समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाले

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार

श्री अमित शाह जी

का

सशस्त्र नक्सल आतंक के खात्मे के बाद
प्रथम बस्तर आगमन पर

हार्दिक स्वागत है

18 मई 2026 | बस्तर, छत्तीसगढ़

छ.ग. डायल - 112
(Phase 2 - Next Gen)
का शुभारंभ
सुबह 10:30 बजे
पी. टी. एस. माना (रायपुर)

जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ
दोपहर 12:00 बजे
नेतानार (बस्तर)

शहीदों को श्रद्धांजलि
दोपहर 1:30 बजे
अमर वाटिका, जगदलपुर (बस्तर)

शहीदों के परिजनों, सुरक्षा बलों, नक्सल पीड़ितों और समाज प्रमुखों से मुलाकात एवं चर्चा
दोपहर 2:00 बजे
बादल अकादमी, जगदलपुर (बस्तर)

संवाद 47837/04

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)